

कांकेर के मोरखंडी जंगल में मिला नक्सल डम्प

कांकेर में जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की.

कांकेर। बस्तर संभाग में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन सुरक्षा बल अब भी तैनात है। जंगलों, पहाड़ों में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि बस्तर के अंदरूनी गांव आईईडी फ्नी विलेज बने। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को कांकेर के मोरखंडी के जंगलों से नक्सल डंप मिला है। हथियार सहित बड़ी मात्रा में सामान मिला है। कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम द्वारा संयुक्त रूप से मोरखंडी के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप का पता चला, जिसके बाद जवानों ने नक्सल डंप अपने कब्जे में लिया।

बरामद सामग्री में भारमार बंदूक 4, भस्मार बंदूक के बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर 1 शामिल हैं। इसके अलावा नक्सल साहित्य एवं अन्य

हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद



सामग्री भी बरामद की गई है।

यह संयुक्त अभियान बस्तर रेंज आईजी बंदी नारायण मीणा, डीआईजी बीएसएफ भानुप्रतापपुर दीपक तिवारी, कांकेर एसपी निखिल राखेचा और 94वीं वाहिनी बीएसएफ बांदे के प्रभारी सेनानी सुभाष चंद्र के मार्गदर्शन में चलाया गया। अभियान में 94वीं वाहिनी बीएसएफ के इंस्पेक्टर हनुमान मीणा, उप निरीक्षक मोहित बंसल तथा बीएसएफ

बीडीएस टीम के कमांडर उप निरीक्षक रोशन लाल मीणा सहित जवान शामिल रहे।

कांकेर पुलिस के मुताबिक सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में जिला बल एवं बीएसएफ की संयुक्त सर्चिंग लगातार जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कटघोरा में दतैल ने रोका डीजल टैंकर

हॉर्न बजते ही टैंकर की ओर दौड़ा हथी, हाईवे पर आधे घंटे जाम

कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क पार कर रहे एक दतैल हथी ने डीजल टैंकर का रास्ता रोक दिया। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और वाहन चालकों में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, डीजल टैंकर कटघोरा की ओर से आ रहा था, तभी जंगल से निकलकर एक दतैल हथी सड़क पर आ गया और टैंकर के सामने खड़ा हो गया। चालक ने हथी को हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो हथी भड़क गया और टैंकर की ओर दौड़ पड़ा। घबराए चालक ने वाहन को पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन टैंकर का पहिया सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया। स्थिति बिगड़ती देख चालक और परिचालक टैंकर छोड़कर जंगल की ओर भाग गए और किसी तरह अपनी जान बचाई।

इस दौरान हथी काफी देर तक सड़क के आसपास ही घूमता रहा। हथी के सड़क पर होने से हाईवे के दोनों ओर



वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में इन दिनों करीब 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग द्वारा हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है। हथी आसपास के खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसान रातभर जागकर फसलों की रखवाली कर रहे हैं और हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं।

वन विभाग की टीम ने गांवों में मुनादी कराकर लोगों को हाथी के करीब न जाने की चेतावनी दी है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। वन विभाग ने वन क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि हाथी की मौजूदगी को सूचना मिलने पर सावधानी बरतें, हॉर्न न बजाएं और हाथी के बेहद करीब जाकर उसे छेड़ने का प्रयास न करें।

रायगढ़ जिला अस्पताल का होगा कायाकल्प

300 बेड के नए भवन में मिलेंगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

रायगढ़। रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल जिला अस्पताल के जर्जर भवन के स्थान पर 100 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड का नया अत्याधुनिक अस्पताल भवन बनेगा। राज्य सरकार ने अस्पताल प्रबंधन के नक्शे को अंतिम मंजूरी दे दी है।

रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल जिला अस्पताल के जर्जर भवन के स्थान पर 100 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड का नया अत्याधुनिक अस्पताल भवन बनेगा। राज्य सरकार ने अस्पताल प्रबंधन के नक्शे को अंतिम मंजूरी दे दी है। चिकित्सालय के आधुनिकीकरण और कायाकल्प की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए परिसर के निर्माण से जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

अस्पताल का पुराना भवन काफी समय से जर्जर स्थिति में था। कम जगह और सीमित सुविधाओं के कारण लंबे समय से नया भवन बनाने की मांग उठ रही थी। सिविल सर्जन डॉ. दिनेश पटेल ने बताया कि शासन से नक्शा मंजूर होकर आ गया है। बारिश का मौसम समाप्त होते ही



300 बेड वाले नए भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। बहुमंजिला इमारत में ओपीडी से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज तक की अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। इसमें विशेष रूप से स्त्री रोग विभाग और शिशु रोग विभाग को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके अलावा गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के त्वरित इलाज के लिए एक अत्याधुनिक बर्न यूनिट भी बनेगी। नए भवन के बेसमेंट में अत्याधुनिक जांच केंद्र और पार्किंग की व्यवस्था होगी। यहां सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोग्र वजन डिजिटल एक्सरे, एक्सरे विभाग, रेडियोलॉजिस्ट कक्ष, अल्ट्रासोनोग्राफी कक्ष और स्टोर रूम का निर्माण होगा। एंटीड्रिग और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी रहेगा। भूतल पर मरीजों की सहूलियत

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर परखेगा राज्य स्तरीय दल

बिलासपुर। कांकोरच जनता पार्टी के स्कूली शिक्षा सुधार आंदोलन का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आया है। सरकारी स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षाओं में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों के सीखने की क्षमता की धरातलीय जांच के लिए राज्य स्तरीय दल का गठन किया है। विभाग ने पहले चरण के अंतर्गत दुर्ग समेत पांच जिलों को इस विशेष जांच अभियान के लिए चुना है। राज्य स्तरीय दल दुर्ग जिले के कम से कम तीन विद्यालयों में पहुंचकर बिना किसी पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान दल के सदस्य खुद कक्षाओं में बैठकर शिक्षकों के पढ़ाने की शैली और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को देखेंगे।

निरीक्षण मुख्य रूप से तीसरी, छठवीं और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों की विषयगत समझ पर केंद्रित रहेगा। जांच दल गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों में बच्चों की समझ और दक्षता की गहराई से परख करेगा। अधिकारी और विषय विशेषज्ञ सीधे बच्चों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि वे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय को कितना समझ पा रहे हैं। दल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञ,



विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानपाठक और व्याख्याता शामिल हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दल स्कूलों को लाल या हरे रंग के संकेत के जरिए फीडबैक देगा। लाल और हरे रंग के इस संकेत के आधार पर जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारी बैठक करके सुधार की कार्ययोजना बनाएंगे। इसके बाद, अधिकारी इस कार्ययोजना को आगे समग्र शिक्षा को भेजेंगे। विभाग ने प्रथम चरण के निरीक्षण कार्यक्रम के लिए दुर्ग के साथ रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का चयन किया है।

दुर्ग में शिक्षा के स्तर का सटीक आकलन

फर्जी ट्रान्सफर के बाद अब नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप

भाजपा महामंत्री के बेटे प्रणव अवस्थी के खिलाफ शिकायत

बलौदाबाजार-भाटापारा।

बलौदाबाजार जिले में फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार कराने के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी के बेटे प्रणव अवस्थी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये एंठने का नया आरोप लगा है। बलौदाबाजार जिले में फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार कराने के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी के बेटे प्रणव अवस्थी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये एंठने का नया आरोप लगा है। महासमुंद जिले के कोमखाव थाना क्षेत्र स्थित ग्राम खेमरा निवासी पीड़ित कलश राम ध्रुव ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर राशि वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायतकर्ता के महासमुंद जिले का निवासी होने के कारण शिकायत को जांच के लिए महासमुंद भेजने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित कलश राम ध्रुव रोजगार की तलाश में भटक रहा



था। इसी दौरान बारनवापारा क्षेत्र के परिचित के माध्यम से उसका संपर्क प्रणव अवस्थी से हुआ। आरोप है कि प्रणव अवस्थी ने शराब दुकान में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे 50 हजार रुपये ले लिए। आरोपी ने पीड़ित से मांग पत्र (डीडी) जमा करने को कहा। पड़ताल करने पर मांग पत्र फर्जी पाया गया, जिस पर पीड़ित ने नौकरी करने से मना कर दिया और अपनी राशि वापस मांगी। इसके बाद आरोपी ने एनईएफसी के जरिये भुगतान की एक रसीद भेजी। हालांकि, बैंक खाते में राशि नहीं पहुंचने पर जांच कराने से एनईएफटी रसीद भी फर्जी पाई गई। पीड़ित ने बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक गौरव राय को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपी प्रणव अवस्थी के

विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और अपनी राशि वापस दिलाने का अनुरोध किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने पीड़ित को महासमुंद जिले का निवासी बताते हुए शिकायत को महासमुंद स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। अब महासमुंद पुलिस स्तर पर शिकायत में दर्ज तथ्यों, दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की जाएगी। आरोपी प्रणव अवस्थी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बलौदाबाजार की पलारी पुलिस ने कंप्यूटर के माध्यम से फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार करने और उसका उपयोग करने के मामले में भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, उनके बेटे प्रणव अवस्थी और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखर कश्यप समेत छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की टपकती छत को मिलेगा इलाज

सरगुजा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का कलेक्टर अजीत वसंत ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में सीपेज की समस्या के साथ ही उन्होंने निर्माणधीन कार्य, शौचालय और किचन का भी निरीक्षण किया।इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के अधीक्षक और डीन को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर अजीत वसंत ने निरीक्षण के बाद बताया कि जिस भवन में सीपेज आ रहा है, उसके लिए नगर निगम को डीएमएफ मद से 50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उसका टेंडर भी हो चुका है। वहीं अस्पताल के डीन अविनाश मेश्राम का कहना है कि कलेक्टर सर ने दौरा किया है।उन्होंने सीपेज और निर्माण कार्यों को देखा।इसके बाद सीपेज सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। खासकर भारी बारिश में सीपेज की समस्या से मरीज और अस्पताल स्टाफ प्रभावित थे। लेकिन पुराने जर्जर भवन को रिपेयर करने का कोई माध्यम समझ नहीं आ था।

पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट न हो: छग हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के

पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि थानों में सिर्फ कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, सीसीटीवी सिस्टम हर समय चालू रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक या तकनीक लापरवाही के कारण इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कहा है। जीपीएम के गौरेला थाने में नशे के कारोबार मामले के आरोपी समेत चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोपियों का दावा था कि घटना से एक दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें थाने में बिठा लिया था। अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच की थाने की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर और टावर लोकेशन उपलब्ध कराने की मांग की। ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने बताया कि 18 महीने की स्टोरेज अवधि पूरी होने के कारण संबंधित सीसीटीवी फुटेज सिस्टम से ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं।

चिंतावागु नदी में तेज बहाव के बीच नगर सेना ने संभाला मोर्चा

बीजापुर। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर ग्रामीणों को नदी-नाले पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जिला प्रशासन एवं राहत-बचाव दल लगातार सक्रिय रहकर ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम चिंताकवाली के पास स्थित चिंतावागु नदी में नगर सेना की टीम ने बोट के माध्यम से ग्रामीणों को सुरक्षित नदी पार करवाया। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के लिए सुरक्षित तरीके से नदी पार करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। आवागमन की इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची और बोट के जरिए ग्रामीणों को नदी के दूसरे छोर तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य शुरू किया। इस दौरान नगर सेना के जवानों ने विशेष सतर्कता बरतते हुए ग्रामीणों को बोट में सुरक्षित बैठाया और तेज बहाव के बीच सावधानीपूर्वक नदी पार कराई।

बिलासपुर में सीनियर सिटीजन से ठगी की कोशिश

बिलासपुर। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठाणों ने 68 वर्षीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर करीब 35 लाख रुपये की ठगी करने की कोशिश की। हालांकि बिलासपुर पुलिस की तत्परता से बुजुर्ग ठगी का शिकार होने से बच गए और बैंक खाते में जमा पूरी राशि सुरक्षित बचा ली गई। मामले ने जानकारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिंका सिंह ने बताया कि 24 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक के एक मित्र ने डीआईजी एवं एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह को मोबाइल फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका पीड़ित दोस्त सरकंडा क्षेत्र के सीपत रोड का निवासी हैं। उन्हें मोबाइल नंबर 9401274963 से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को सुनील कुमार गौतम डुक्क, बारबानकी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में फंसे होने का डर दिखाया। ठगों ने लगातार वीडियो कॉल और बातचीत के जरिए उन्हें डराया और कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट में रखने का झांसा दिया।

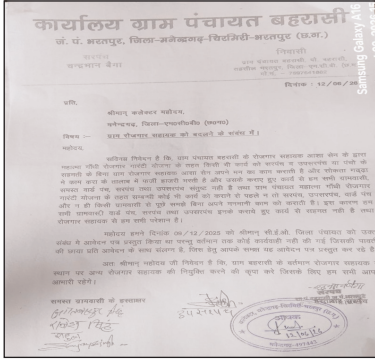
भिलाई में ट्रान्सपोर्टर के ठिकानों पर जीएसटी की रेड

दुर्ग। भिलाई में स्टेट बस्स की टीम ने सोमवार को हैवी ट्रान्सपोर्ट कंपनी (HTC) के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोट्टू से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की. तस्ख अधिकारियों की टीम ने कंपनी के ऑफिस और गोदाम में पहुंचकर दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच शुरू की। इसी दौरान एक टीम बलौदाबाजार स्थित कंपनी के यार्ड में भी जांच के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच तस्ख विभाग की टीम भिलाई स्थित कंपनी के ठिकानों पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान 24 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग स्थानों पर जांच में जुटे रहे। टीम ने कंपनी के कारोबार से जुड़े दस्तावेज, तस्ख रिकॉर्ड, लेन-देन और अन्य जरूरी कागजातों को खंगाला। बताया जा रहा है कि हैवी ट्रान्सपोर्ट कंपनी के पास 1500 से ज्यादा ट्रक हैं। ऐसे में तस्ख विभाग की जांच कंपनी के बड़े कारोबारी नेटवर्क और वाहनों के संचालन से जुड़े रिकॉर्ड पर भी केंद्रित है। अधिकारियों की टीम यह भी देख रही है कि कंपनी के कारोबार और वाहनों से संबंधित तस्ख रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी सही है या नहीं।

एमसीबी में रोजगार सहायक को हटाने की मांग

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ग्राम पंचायत बहरासी में डूकृत ऋतूव योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सरपंच चंद्रभान बैगा और उपसरपंच सहित पंचों ने रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक मनमाने तरीके से कार्य करा रहे हैं, ग्रामीणों और सरपंच से कोई सलाह मशविरा तक नहीं किया जा रहा है। सरपंच और उपसरपंच सहित पंचों का आरोप है कि मजूरों को भुगतान भी नियत समय पर नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि डूकृत ऋतूव योजना के तहत कराए जा रहे कामों में कथित रूप से अनियमितता बरती जा रही है।

ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित रोजगार सहायक को यहां से हटाकर कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। सरपंच चंद्रभान बैगा का कहना है कि उन्होंने 12



जून 2026 को ही कलेक्टर से इस बात की शिकायत आवेदन के जरिए की थी। उससे पहले 9 दिसंबर 2025 को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है। वहां से कार्रवाई नहीं होने पर 12 जून को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीबी-जी-राम-जी

कार्य के दौरान 45 मजदूरों के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी हाजिरी बनाई गई। इससे जुड़े दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। संबंधित अधिकारियों से हमने इस बात की शिकायत की। शिकायत के बाद जांच टीम गांव पहुंची थी। लेकिन ग्रामीणों के सामने जांच में फर्जी हाजिरी और गड़बड़ी से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई। चंद्रभान बैगा, सरपंच ग्राम पंचायत बहरासी के सरपंच चंद्रभान बैगा ने रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, रोजगार सहायक के पति द्वारा भी पंचायत के कार्यों में दखल दिए गए और कथित तौर पर अनियमितताएं किए जाने की शिकायत है। संबंधित रोजगार सहायक पर नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसे कहीं पदस्थ कर दिया जाए। जनपद पंचायत भरतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने कहा, मामले में जिला स्तर की टीम जांच के लिए गांव

पहुंची थी, जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जिला पंचायत सीईओ के स्तर से दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वीबी-जी राम जी योजना का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन। केंद्र की मोदी सरकार की यह नई ग्रामीण रोजगार योजना है।

1 जुलाई 2026 से ये पूरे देश में लागू हुई। केंद्र सरकार का कहना है कि इस नई योजना के तहत मजदूरों के हितों को पहले से ज्यादा सुरक्षित रहता है। योजना के तहत मजदूरों को पहले की अपेक्षा रोजगार के ज्यादा दिन भी मिलेंगे।

पहले ये योजना मनरेगा के नाम से चल रही थी। मनरेगा में जहां 100 दिनों का काम लोगों को मिलता था, वहीं वीबी-जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम मजदूरों को मिल रहा है।

15 घंटे बाद देवघरही में फंसे तीनों युवकों को सुरक्षित निकाला

कोरबा। देवघरी वाटरफॉल के पास फोटो खिंचने पहुंचे तीन युवक अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच टापू पर फंस गए। करीब 15 घंटे तक रातभर तेज बहाव और अंधेरे के बीच फंसे रहने के बाद आज सुबह पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। युवकों को रस्सी के सहारे नदी पार कराकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। फंसे युवकों की पहचान धनेश्वर साथी, घनश्याम महंत और सूरज सारथी के रूप में हुई है। तीनों गुरमा श्यांग के रहने वाले बताए गए हैं। वे सतरंगा घूमने के बाद देवघरही वाटरफॉल पहुंचे थे। यहां



फोटो खींचने के दौरान अचानक नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ गया, जिससे वे रास्ते में बने टापू पर फंस गए। पानी बढ़ने के बाद तीनों युवकों ने टापू के बीच बनी एक छतरी में शरण ली। रात के समय वहां अंधेरा था और नदी का बहाव तेज होने के कारण उनके लिए बाहर निकलना संभव नहीं था। युवकों ने रेस्क्यू टीम से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए रखा और अपनी लोकेशन की जानकारी देते रहे। रेस्क्यू टीम ने उन्हें घबराने से बचने और बहाव बढ़ने की स्थिति में

सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी। टॉच की रोशनी के जरिए उनकी लोकेशन पर नजर रखी गई। सुबह मौसम और पानी की स्थिति का आकलन करने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। टीम ने रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव को पार कराते हुए तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 15 घंटे तक चले इस रेस्क्यू के बाद तीनों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया, फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज बारिश और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के दौरान जलप्रपात और नदी के आसपास पिकनिक या घूमने के लिए न जाएं।

संक्षिप्त समाचार

रूपकुमारी चौधरी ने संभाली भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी

रायपुर/ नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी



महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासमृद्ध लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने आज महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानाथी श्रीनिवासन एवं सुश्री सरोज पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही। रूपकुमारी चौधरी की नियुक्ति 17 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा घोषित पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में की गई थी। उन्हें वानाथी श्रीनिवासन के स्थान पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के साथ छत्तीसगढ़ की भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इसी नई टीम में छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्क को पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी भी दी गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की भेंट

रायपुर। महिला अधिकारों के संरक्षण,



महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर विस्तार से महत्वपूर्ण चर्चा हुई। डॉ. ममता साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल एवं प्रभावी आयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों, उनके संरक्षण से जुड़े प्रावधानों तथा उपलब्ध सहायता तंत्र की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रस्तावित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने तथा जमीनी स्तर पर जागरूकता को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

बैंक मैनेजर ही हो गया ठगी का शिकार, दो करोड़ की एफडी का झांसा देकर जीता भरोसा

रायपुर। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज ने भारतीय स्टेट बैंक की आईजीकेवी शाखा की बैंक मैनेजर को ही ठगी का शिकार बना लिया। आरोपी ने खुद को कार कंपनी का संचालक बताकर करीब 2 करोड़ रुपये की एफडी कराने की बात कही और बैंक मैनेजर का भरोसा जीता। इसके बाद मेडिकल धुगतान के नाम पर 4 लाख 99 हजार रुपये दूबरे बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। बैंक मैनेजर श्वेता शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज किया है। वहीं, अब पुलिस मोबाइल नंबर, ई-मेल और बैंक खाते से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटाकर आरोपी की पहचान और ठगी की रकम के लेनदेन की जांच कर रही है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, 20 अगस्त को श्वेता शर्मा के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया। कॉल रिसीव नहीं होने पर उसने मैसेज भेजकर संपर्क किया। आरोपी ने अपना नाम प्रशांत मंधान बताया और खुद को इंटरा कार कंपनी का संचालक बताया। 21 अगस्त को उसने करीब 2 करोड़ रुपए की एफडी कराने की इच्छा जताई और ब्याज दर जानकारी ली। बैंक मैनेजर ने 6.45 प्रतिशत ब्याज दर बताई। आरोपी ने सोमवार को बैंक आने की बात कही।

प्रदेश में लक्ष्य का 97 प्रतिशत बोनी पूर्ण

रायपुर। प्रदेश में खेती किसानों का कार्य जोरों पर है। राज्य में 25 अगस्त की स्थिति में राज्य के 47.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का 97 प्रतिशत बोनी पूर्ण हो चुकी है। इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश किसानों को सुगमता से मिले खाद-बीज मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती-किसानी में सहूलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा है।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग का रोडमैप तैयार, मंत्री राजेश अग्रवाल बोले-

नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण जारी

■ चित्रकोट में 25 करोड़ की लागत से बनेगी टेंट सिटी

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल और विभागीय सचिव डॉ. एस. भारती दासन ने आज छत्तीसगढ़ संवाद के ऑफिडोटोरियम, अटल नगर, नवा रायपुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक स्थलों और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की।

मंत्री राजेश अग्रवाल और सचिव भारती दासन ने बताया कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चित्रकोट के पास 25 करोड़ रुपये की लागत से टेंट सिटी विकसित करने की योजना है। चित्रकोट को भारत सरकार की 'वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' पहल के तहत प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए 45 युवाओं को आईआईटीटीएम ग्वालियर से निशुल्क गाइड



ट्रेनिंग दिलाई गई, जिनमें 9 युवाओं को रिसॉर्ट और पर्यटन सूचना केंद्रों से जोड़ा गया है। प्रदेश में होमस्टे पॉलिसी 2025-30 लागू है और 7 जिलों के 85 लोगों का होमस्टे विकास के लिए चयन किया गया है। वहीं नवा रायपुर में 350 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण जारी है और छत्तीसगढ़ में बनने वाली फिल्मों को सब्सिडी देने की योजना पर भी काम चल रहा है।

धार्मिक पर्यटन को विस्तार देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अगले चरण में 31 स्थानों का चयन किया गया है। पिछले ढाई साल में कलाकार कल्याण कोष के तहत 70 कलाकारों को 30 लाख रुपये, लोक

कलाकार प्रोत्साहन योजना में 87 कलाकारों को करीब 19 लाख रुपये और वरिष्ठ कलाकार-साहित्यकारों को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में 82 लाख रुपये दिए गए हैं।

पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉ. तीन बार्ड के सम्मान में राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है। सरकार का उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि कलाकारों को सम्मान और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। भौगोलिकसंदर्भ

सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करने की पहल, पुरखीती मुक्तानग में लाइट एंड साउंड शो, पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व डिजिटलीकरण पर काम जारी है। वहीं आरंग के रीवा के मुक्तिकागढ़ में पुरातात्विक उत्खनन से 2,750 साल पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण सामने आए हैं।

फुंडहर गौठान में क्षमता से दोगुने से अधिक गौवंश मिलने पर भड़कीं महापौर मीनल चौबे



मौके पर लगभग 560 गौवंश पाए गए। इस पर महापौर ने अधिकारियों से स्पष्ट सवाल किया।

जब गौठान की क्षमता 260 गौवंश की है, तो यहां 560 गौवंश कैसे पहुंचे? इतनी बड़ी संख्या में गौवंश को रखने की व्यवस्था किस आधार पर की गई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? महापौर ने कहा कि क्षमता से अधिक गौवंश होने की स्थिति में चारा-पानी, साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित रखरखाव प्रभावित हो सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं गौठान संचालक को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने तथा गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फुंडहर गौठान से जुड़े रिकॉर्ड में भी निरीक्षण के दौरान फुंडहर गौठान में निर्धारित क्षमता से दोगुने से अधिक गौवंश पाए जाने पर महापौर मीनल चौबे ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। गौठान की क्षमता लगभग 260 गौवंश की है, जबकि

महतारी वंदन योजना से मिल रही आर्थिक मजबूती

रायपुर। शुक्रवारो बाई शासन की योजनाएं जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचती हैं, तो वे केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं रहतीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई राह भी खोलती हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी कोरबा के ग्राम सोनपुरी की रहने वाली शुक्रवारो बाई की है, जिनके जीवन में छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना आर्थिक संबल का आधार बनी है।

शुक्रवारो बाई के बैंक खाते में महतारी वंदन योजना के तहत हर माह एक हजार रुपये की राशि नियमित रूप से पहुंच रही है। वे इस राशि को प्रतिमाह निकालने के बजाय सामान्यतः दो से तीन माह में एक साथ निकालती हैं और घर-परिवार की आवश्यकताओं में इसका उपयोग करती हैं। परिवार में उनके पति मजदूरी का कार्य करते हैं। सीमित आमदनी के बीच शासन से मिलने वाली यह नियमित सहायता परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक



सहारा बन गई है।

शुक्रवारो बाई बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी घरेलू जरूरतों के लिए भी परिवार की आय पर निर्भर रहना पड़ता था। अब हर महीने खाते में आने वाली राशि से उन्हें अपने खर्चों को व्यवस्थित करने में सुविधा होती है। घर की जरूरत का सामान खरीदने से लेकर अन्य आवश्यक घरेलू खर्चों में वे इस राशि का उपयोग करती हैं। उनके लिए, यह राशि केवल एक हजार रुपये नहीं, बल्कि अपने हाथ में मौजूद आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास का माध्यम है।

इस बार रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवारो बाई के लिए कुछ खास होने वाला है। उन्होंने तय किया है कि महतारी वंदन

योजना से बचाकर रखी गई राशि का उपयोग इस बार अपने लिए करेंगी। उनका कहना है कि आमतौर पर महिलाएं अपनी जरूरतों से पहले परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन इस बार वे शासन से मिली इस राशि से अपने लिए आवश्यक सामान खरीदेंगी और रक्षाबंधन का त्योहार अपने लिए भी खुशी के साथ मनाएंगी। शुक्रवारो बाई महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में हर माह राशि पहुंचाने से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। वे मुख्यमंत्री श्री साय को स्नेहपूर्वक 'भैया' कहते हुए भावुक होकर कहती हैं कि उन्होंने अपनी बहनों का ख्याल रखा है। उनके अनुसार, नियमित रूप से खाते में राशि आने से महिलाओं को यह भरोसा मिला है कि वे अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं।

शक्कर, तेल, प्याज, खाद्य सामग्री की महंगाई से त्योहार कैसे मनेगा : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि राखी के त्योहार में शक्कर एवं खाद तेलों की बढ़ती कीमतों ने त्योहार का मजा फीका कर दिया है। आम आदमी त्योहार कैसे मनाये। पिछले एक पखवाड़े में शक्कर की कीमत में 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खाद तेल के दाम दुगुने हो गये है। प्याज 50 रु. किलो पहुंच गया है। आम गृहणी की रसोई की बजट बिगड़ गया है। अच्छे दिनों का वादा कर सरकार में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से परेशान कर रखा है। दाल की कीमते दोगुनी हो गई है, लहसुन 400 किलो, आलू, प्याज, टमाटर एवं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दाल की कीमते दगुनी हो गयी है। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी, घटते इनकम से लोग परेशान हैं वहीं दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही महंगाई बेलगाम हो चुकी है। 1 डॉलर की कीमत 96 रुपये तक पहुंच गया है। केंद्र की मोदी सरकार आम जनता से डीजल, पेट्रोल का डेढ़ गुना दाम वसूल रही है। रसोई गैस की कीमतें तीन गुना अफिल वसूली जा रही है। दूध, दही, पनीर, आटा, मैदा, सूजी,

दलहन तिलहन, कपड़े जैसे दैनिक उपभोग की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ गये है। दवाओं और अस्पतालों तक में इलाज महंगा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार जनता की जेब में खुलेआम डकैती कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी सहित पूरे राज्य में अपराधी और अपराध बेलगाम हो गये है। कल राजधानी में एक ही थाना क्षेत्र में दो अलग अलग चाकू चाकू बाजी की घटनाओं में दो युवकों की हत्या हो गई। इसके पहले एक युवती के साथ सड़क पर घर वापस आते समय गैंग रैप हो गया, कुछ दिन पहले एक औरत के साथ एक दिन में दो बार गैंग रैप हो गया। पिछले 20 दिन में अकेले राजधानी में 12 हत्याएं हुई हैं। राजधानी में रोज आधा दर्जन चाकूबाजी का घटना होती है। कमोवेश यही हालत पूरे प्रदेश की है। ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां रोज हत्या बलात्कार की घटना न हो रही हो। प्रदेश में हर दिन 88मिनक बलात्कार की घटना हो रही है। गृह मंत्री रोज मीडिया से बात करते है लेकिन बढ़ते अपराध पर चुप हैं। उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही। मुख्यमंत्री से तो अब जनता ने उम्मीद नही की छोड़ दिया है।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। नीति आयोग ने देश के 18 राज्यों के वित्तीय स्थिती के बारे में जो रिपोर्ट जारी किया है। उसमें छत्तीसगढ़ 17वें नंबर पर है। राज्य का राजकोषिय घाटा तय लक्ष्य 2.99 से बढ़कर 5.32 हो गया है। नीति आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिती दिवालियो होने की है। इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण जारी करे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2023-2024 के आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम की दूसरी सूची लगभग 1600 पदों की सरकार घोषित नही कर रही है। सूची

मांग आधारित आवासीय परियोजनाओं से हितग्राहियों को मिलेगा लाभ : चौधरी

रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12 फेस-2 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 119.89 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का भूमिपूजन किया। मंत्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत एचआईजी एवं एमआईजी श्रेणी के कुल 348 भवनों का निर्माण किया जाएगा। आवासों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसी सेक्टर में आगामी चरण में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा।

मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय कर्ज से जूझ रहे मंडल को लगभग 700 करोड़ रुपए का ऋण चुकाकर कर्जमुक्त किया गया। इसके बाद मंडल की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए यह नीति निर्धारित की गई कि बिना मांग के किसी स्थान पर



आवासीय परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी परियोजना में 60 प्रतिशत बुकिंग होने अथवा प्रथम तीन माह में 30 प्रतिशत बुकिंग होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे मांग आधारित और व्यावहारिक आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा बिना मांग के निर्मित होकर लंबे समय तक खाली रहने वाले भवनों की समस्या से भी निजात मिलेगी। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

वनवासियों का हित और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : वन मंत्री कश्यप

■ तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता पर जोर, कांटेर में भालू के हमलों को रोकने बनेगी विशेष कार्ययोजना

रायपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 322वीं बैठक आयोजित हुई। यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्री श्री कश्यप के निवास/कार्यालय में आयोजित थी। बैठक में वर्ष 2026 में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेंदूपत्तों के विक्रय के लिए द्वितीय चरण की कार्यवाही तथा वर्ष 2025 सीजन के क्रेता करारनामा समाप्त तेंदूपत्ता लॉट के विक्रय के लिए प्राप्त निविदाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वन बल प्रमुख श्री अरूण कुमार पाण्डेय, एमडी वनोपज संघ श्रीमती संजीता गुप्ता, प्रभारी अपर प्रधान वन संरक्षक श्री एस. जगदीसन, प्रधान वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री ओ.पी.



यादव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री माधेश्वरन व्ही. कार्यकारी निदेशक वन श्री एस.वेंकटचलम् सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तेंदूपत्ता व्यापार, क्रेताओं की नियुक्ति, वनोपजों की बिक्री और वन्यजीवों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री कश्यप ने वनवासियों के आर्थिक हितों के साथ उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों के आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ

काम कर रही है। तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णयों से संग्राहकों को लाभ मिलेगा। वहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में वर्ष 2026 सीजन में संग्रहित और भंडारित तेंदूपत्ता लॉटों के विक्रय की समीक्षा की गई। 4 अगस्त 2026 को हुई द्वितीय चक्र की ऑनलाइन ई-निविदा के आधार पर 40 लॉट के लिए 15 खरीदारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।

बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

■ डीडी नगर थाने का किया घेराव, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटेी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडी नगर थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने शहर में लगातार हो रही हत्या, नशे के कारोबार और अन्य अपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

कांग्रेस का दावा है कि 1 अगस्त से 25 अगस्त के बीच राजधानी रायपुर में हत्या की 12 घटनाएं सामने आई हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ रही अपराधिक घटनाओं से आम लोगों में भय का माहौल है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में डीडी नगर थाना क्षेत्र में सामने आए डबल मर्डर और बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी के मामले का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजधानी में अपराध और नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस इन पर प्रभावी



तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। डीडी नगर थाने के घेराव में जिला कांग्रेस कमेटेी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, प्रदेश कांग्रेस कमेटेी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राजधानी में कानून-व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि राजधानी में लगातार सामने आ रही हत्या और नशे से जुड़ी घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने पुलिस से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

घोटने से 6 गाय मर गई। दस हजार गौठान के जगह मात्र 1400 गौ धाम बनाने का जा रहे, उसमें भी अभी लगभग 64 का ही काम शुरू हुआ है। ऐसे में गाय कहा जाएगी। गाय सड़कों पर आकर मर रही और उनके कारण सड़क दुर्घटनाएं अलग हो रही और खुले पशु के कारण किसान चराई से परेशान हो रहे। सरकार गायों संरक्षण के मामले में फेल हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट सहित देश के 11 और हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को देने जा रही है। सरकार विभागों की संवत्तियां नवकर कंपनियां और देश के संसाधनों को लगभग बेचने वाली मोदी सरकार ने इससे पहले भी कई हवाई अड्डों में हिस्सेदारी बेची है और अनेकों एयरपोर्ट में निजी कंपनियों को बिना लागत लगाए संचालन के नाम पर वसूली का काम सौंप दिया है। इसके पहले भी देश के बड़े अनेकों एयरपोर्ट को जीएमआर, अडानी समूह को बेचा जा चुका है। अब रायपुर की बारी आ गयी। मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने पूरे देश के संसाधन बेचने में लगी है।

अमेरिका के साथ ईरान का नया माइंड गेम!

विकास मिश्रा

अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एक वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस वीडियो को ईरान के सरकारी टेलीविजन ने जारी किया है। इसमें ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही एक भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं। इस वीडियो में बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल देखी जा सकती हैं। संकेत बहुत साफ है कि यह वीडियो अपने दुश्मन देशों को चिढ़ाने के लिए ही ईरान ने जारी किया है। इस वीडियो के साथ ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह दावा भी दोहराया जा रहा है कि ईरान ने अटैंक ड्रोन का उत्पादन तीन गुना कर दिया है। हालांकि कई विशेषज्ञ यह दावा करते रहे हैं कि ईरान की सामरिक क्षमता को कम करके आंकना बड़ी भूल हो सकती है। जंग शुरू होने के बाद ईरान की मिसाइलों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हालांकि यह दावा करते रहे हैं कि ईरान की सामरिक क्षमता को तहस-नहस कर दिया गया है। उनके दावे का आधार अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमले हैं। जंग शुरू होने के बाद से इन दोनों देशों ने ईरान पर छह हजार से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। करीब 3400 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन ठिकानों में परमाणु संयंत्रों के साथ ही मिसाइल निर्माण फैक्ट्री और अन्य सैन्य ठिकाने रहे हैं। हालांकि वास्तविक आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं। इसके बावजूद ईरान मिसाइल फैक्ट्री के वीडियो जारी करके मिसाइलों का खजौरा दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वह अमेरिका को बताना चाह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। हालांकि इस वीडियो पर अभी तक अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है लेकिन दोनों देश इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है। चीन और रूस भले ही इनकार कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों ही देश ईरान की भरपूर मदद कर रहे हैं। दुनिया की खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि चीन से बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट ईरान के लिए सोडियम परक्लोरेट जैसी जरूरी रासायनिक सामग्री ईरान को मिल रही है। इतना ही नहीं, चीन से शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस और शॉल्टर-फायर मिसाइल सिस्टम भी ईरान को मिले हैं। खुफिया एजेंसियों को इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि रूस कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को गोला-बारूद, ड्रोन के पुर्जे और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति कर रहा है, रूस से मिली इस विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल वह अपने मिसाइल और ड्रोन वारहेड में कर रहा है। चीन और रूस की मंशा बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका इस जंग में जितना उलझा रहेगा, आर्थिक रूप से उसे उतना ही झटका लगेगा। ईरान जिस ड्रोन से हमला करता है, उसकी कीमत केवल 30 हजार डॉलर से लेकर 50 हजार डॉलर तक होती है जबकि इसे नष्ट करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका करता है वह कई लाख डॉलर की होती है। यानी अमेरिका को ईरान का हर ड्रोन लाखों डॉलर का झटका दे जाता है। यहां एक सवाल सबके मन में यह भी उठता रहा है कि क्या ईरान की मदद नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है। सीधे तौर कर इस सवाल का जवाब उपलब्ध नहीं है लेकिन नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच सामरिक महत्व की साझेदारी गुपचुप रूप से रही है। माना यह जाता है कि ईरान की मिसाइल प्रणाली को विकसित करने में और परमाणु संयंत्रों के निर्माण में नॉर्थ कोरिया सहयोग देता रहा है। हालांकि इस जंग में उत्तर कोरिया हथियारों की आपूर्ति सीधे नहीं कर रहा है लेकिन रूस के साथ उसका सहयोग खूब चल रहा है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यदि हम आधुनिक गवेषकों से सूर्य के उपर्युक्त काले धब्बे का कारण पूछे तो वे कुछ भी नहीं बता सकेंगे, परन्तु पुराण-साहित्य में तो इस बात का भी कार्यकारण-पुस्सरर लौकिकी भाषा में स्पष्टी-करण किया गया है, यथा-

(क) विश्वकर्मा ह्यनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः ।
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शतयामास तस्य वे ।।

(भविष्यपुराण ब्राह्म 76 । 51)

(ख) छाया शनैन्चरं लेभे ।

(श्रीमद्भागवत 6।6।41)

अर्थात्- (क) विश्ववकर्मा भगवान् ने शाकद्वीप में विवस्वान् सूर्य्य को अपने भ्रमि नामक यन्त्र पर चढ़ा कर उसका प्रखर तेज छील डाला ।

(ख) सूर्य्य की अर्धाङ्गिनी छाया से शनैश्चर पैदा हुआ ।

तात्पर्य्य यह हुआ कि सृष्टिरचना के समय सूर्य्य

पिण्ड आकर्षण विकर्षण के चक्र में पड़ कर अपने बहुत से भास्वर भाग को खो बैठा ।

सूर्य्य पिण्ड के जिस भाग की भास्वरता विनष्ट हुई थी वह भाग हमारी पृथ्वी के शाकद्वीप (= वर्तमान आस्ट्रेलिया) की ठीक सामने की कक्षा में पड़ता है। सूर्य्य का जो भाग टूटा था वही समय पाकर शनैश्चर नामक ग्रह हुवा ।

इसीलिए पुराणों में उसे सूर्यपुत्र कहा है। सूर्य का भग्नावशेष खण्डहर ही छाया है जिसे आधुनिक अनुसन्धा-यक काला धब्बा बताते हैं। इस तरह पुराणों में इस काले धब्बे का सभी रहस्य विस्तारपूर्वक प्रकट किया गया है ।

छन्द:शास्त्र

अग्निपुराण में (अध्याय 328 से 335 पर्यन्त)

छन्द:शास्त्र का समावेश है, इसमें लौकिक और वैदिक छन्दों के भेद का अद्वितीय वर्णन है ।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

आरक्षण : जंतर-मंतर की सियासी झाड़फूंक

कमलेश पांडे

नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक धरना-प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर (वोट क्लब के बाद) पर 21 अगस्त 2026 को हुआ ‘आरक्षण हटाओ’ आंदोलन वास्तव में आरक्षण सुधार मुहिम बनकर रह गया। हालांकि इसके सामाजिक मिजाज और जनहितकारी त्वेरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए महज एक और धरना नहीं है, बल्कि यह उस असंतोष की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में अवसरों को लेकर सामान्य वर्ग के एक प्रतिभाशाली हिस्से, खासकर जेन-जी युवाओं में दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रौढ़ और बुजुर्ग समाजसेवियों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है।

इसलिए जंतर-मंतर की सियासी झाड़फूंक पर गौर फरमाना आवश्यक है, क्योंकि संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है जो कब खत्म होगी, शायद नेताओं को भी नहीं पता, क्योंकि दो नावों की सवारी करने में वे माहिर जो होते हैं। कहना न होगा कि जिस तरह से 21 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचे और अनुमति न मिलने के बावजूद 22 अगस्त को भी प्रदर्शन जारी रहा और दिल्ली पुलिस द्वारा 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट सामने आई, उसने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन की पक्षपाती भूमिका का भी पर्दाफाश कर दिया।

इससे सामान्य वर्ग के आन्दोलनकारियों, जो मोदी सरकार के प्रबल समर्थक लोगों में शुमार किये जाते हैं, को यूजीसी मुहिम के बाद आरक्षण सुधार मुहिम के रूप में दूसरा बड़ा धक्का लगा। वस्तुतः, प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक वंचना को अधिक महत्व दे। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है, वह यह कि-

पहला यह कि, जब अपनी सरकार से आरक्षण पर सवाल पूछना अपराध नहीं है तो फिर दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर अनुमति क्यों नहीं दी? फिर शांतिपूर्ण लोगों पर बल प्रयोग और गिरफ्तारी क्यों की गई? इस जनप्रदर्शन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरक्षण पर असहमति को अपने-आप सामाजिक न्याय-विरोधी मानने के बजाय इसे सार्वजनिक नीति की बहस के रूप में देखने की गुंजाइश दिखाई देती है। यह distinction



महत्वपूर्ण है।

जैसे आरक्षण की आलोचना करना और वंचित वर्गों के अधिकारों का विरोध करना एक ही बात नहीं है। उसी तरह, आरक्षण का समर्थन करना और आरक्षण व्यवस्था के हर वर्तमान प्रावधान को सही मानना भी एक ही बात नहीं है। यही वह बीच का क्षेत्र है जहां गंभीर पत्रकारिता और नीति-विमर्श होना चाहिए। यद्यपि जंतर-मंतर के आंदोलनों और पत्रकारों से जुड़े घटनाक्रम पर अलग से कतिपय कार्यक्रम भी सामने आया है। इससे उनका व्यापक दृष्टिकोण समझने में मदद मिलती है कि वे आंदोलन को केवल तत्काल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि उसके पीछे के सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखते हैं।

दूसरा यह कि आंदोलन की सबसे मजबूत दलील क्या है? आंदोलनकारियों का सबसे मजबूत प्रश्न है- अगर गरीबी सभी जातियों में मौजूद है, तो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की मदद केवल उसकी जाति देखकर क्यों तय हो? यह सवाल भावनात्मक होने के साथ-साथ नीतिगत भी है।

प्रदर्शन में मेरिट, आर्थिक आधार और आरक्षण नीति पर श्वेत पत्र की मांग उठी। यह मांग आरक्षण को असहज कर सकती है क्योंकि इससे बहस सीधे आंकड़ों पर आ जाएगी- आरक्षण का वास्तविक लाभ किसे मिला? किन परिवारों को पोटियों से लाभ मिल रहा है? कौन से समुदाय अभी भी प्रतिनिधित्व से बाहर हैं? आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर हैं या नहीं? सरकारी नौकरियां इतनी हैं भी या नहीं कि आरक्षण की पूरी बहस को केवल कोटे के प्रश्न तक सीमित किया जा सके? इसलिए श्वेत पत्र की मांग को केवल आरक्षण-विरोधी नारा मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा।

तीसरा यह कि, लेकिन आंदोलन की सबसे बड़ी वैचारिक कमजोरी भी यहीं है। सिर्फ गरीबी सामाजिक पिछड़ेपन का पूरा मापदंड नहीं है।

किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदल सकती है, लेकिन सामाजिक पहचान और उससे जुड़े भेदभाव के अनुभव हमेशा उसी गति से नहीं बदलते।

यही आरक्षण समर्थक पक्ष की मूल दलील है। इसलिए यदि आंदोलन यह मान ले कि गरीबी = पिछड़ापन तो उसका तर्क अधूरा रह जाएगा। भारत में आरक्षण केवल गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि इसका संबंध सामाजिक प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को संस्थागत अवसर देने से भी है। इसीलिए आर्थिक सहायता और आरक्षण को पूरी तरह समानार्थी मानना संवैधानिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से समस्या पैदा करता है।

चौथा यह कि, चिराग पासवान जैसेों की प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? गत 22 अगस्त को चिराग पासवान ने आरक्षण को खेरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि यह किसी आंदोलन के कहने मात्र से समाप्त नहीं हो सकता। राजनीतिक दृष्टि से यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एक ओर सामान्य वर्ग के युवाओं में असंतोष बढ़ता है, तो दूसरी ओर एससी/एसटी/ओबीसी राजनीतिक समूहों के लिए आरक्षण केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए कोई भी राष्ट्रीय दल सीधे तौर पर एक पक्ष चुनकर दूसरे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यही वजह है कि भाजपा सहित सभी दलों के सामने आने वाले समय में कठिन सामाजिक-संतुलन की चुनौती होगी। जबकि वास्तविकता यह है कि इसी आरक्षण को आड़ में कतिपय दलित/आदिवासी परिवार फल फूल रहे हैं और अपने ही वर्ग के वंचित लोगों की हकमारी कर रहे हैं। चूँकि संसद और सुप्रीम कोर्ट अबतक इनके पक्ष में है, इसलिए ये वास्तविक दलितों/आदिवासियों को फलने फूलने के मौके नहीं दिए और इसके लिए मनुवादियों यानी सामान्य वर्ग के लोगों को जिम्मेदार ठहराकर अपना सियासी हित साधते आए हैं। मौजूदा आंदोलन से यह स्थिति भी बदलेगी।

पांचवां यह कि, ब्रजेश पाठक का हस्तक्षेप भी राजनीतिक संकेत है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आंदोलनकारी छात्रों के नेता हर्ष दुबे से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को आगे पहुंचाने और केंद्रीय मंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया। यह छोटा घटनाक्रम नहीं है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि



लोरेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। वहीं साल 1946 में मदर टेरेसा को आध्यात्मिक अनुभव महसूस हुआ और फिर स्कूल में पढ़ाना छोड़कर कोलकाता के गरीबों, लावारिसों और बीमार लोगों की सेवा करने लगीं। इसके बाद उन्होंने कभी

पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार गरीबों और बीमारों की सेवा में लगी रहीं। जब मदर टेरेसा सेवा क्षेत्र में आईं तो उन्होंने अपनी ड्रेस साड़ी कर ली। जिससे कि वह भारतीय सभ्यता के बीच आसानी से घुल-मिल सकें। इससे पहले वह झोपड़ी में रहा करती थीं और भीख मांगकर अपना पेट भरती थीं। उन्होंने कोढ़, प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की सेवा में साल 1947 में मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ले ली थी।

मदर टेरेसा ने भारत की बेटी बनकर की मानवता की सेवा

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 26 अगस्त को महान संत और समाजसेवी मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में रहकर गरीबों की सेवा में बिता दी थी। उन्होंने अपने कार्यों से पूरी दुनिया में मानवता की सेवा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। मदर टेरेसा ने बचपन में ही गरीबों और असहायों की सेवा करने का मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अल्बानिया से आयरलैंड जाकर प्रशिक्षण भी लिया था।

मेसेडोनिया के स्कोप्जे में एक अल्बेनीयाई परिवार में 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। उनके पिता एक साधारण व्यवसायी थे। उनका असली नाम एनेस था, जिसको बदलकर उन्होंने अपना नाम टेरेसा रख लिया था।

यह नाम चुनने के पीछे एक खास वजह थी, क्योंकि वह संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थीं। पढ़ाई के साथ ही उनको संगीत में दिलचस्पी थी। जब मदर टेरेसा 12 साल की थीं, तभी इनको अनुभव हो गया था कि वह अपना जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। वहीं 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया।

बता दें कि 06 जनवरी 1929 को मदर टेरेसा भारत आ गई थीं। यहां पर वो मिशनरी के रूप में गरीबों और बीमारों की सेवा करने लगीं। दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने बंगाली सीखी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का कार्य शुरू किया। फिर उन्होंने कोलकाता में 20 साल तक एनटैले के

मुनीर शीर्ष पर बैठ गए हैं और उत्तराधिकारियों की पूरी कतार उन्होंने रोक दी है।

नया कानून कुछ को डराएगा और कुछ के लिए उम्मीद लाएगा। इस कानून का इससे बेहतर नाम शायद ‘पाकिस्तान डिफेंस (चाटुकारिता पसंदगी) एक्ट’ हो सकता है। मुनीर ने अपने वफादार सैन्यद आमिर रजा को हाल में पदोन्नत कर फोरे-स्टार जनरल और नवगठित नेशनल स्ट्रैटजिक

कमांड का कमांडर बनाया है। नए कानून से रजा तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक मुनीर चाहेंगे। सबसे पुराना सच यह रहेगा है कि सभी तानाशाह अकेले और डरे हुए होते हैं। मुनीर के डर को परिभाषित करने के लिए बेहतर शब्द एक्रोफोबिया (ऊंचाई से डर) होगा। वह बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आगे कहां जाना है और इस बीच जो दुश्मन बनाए हैं, उनका खटका उन्हें लगा रहता है। मुनीर के रूतबे की बात करें तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय शक्ति उसकी सेना पर आधारित है। अर्थव्यवस्था मृतप्राय है और उसे उबारने के कोई कोशिश भी नहीं दिखती। अब सऊदी अरब से ही किसी बड़ी आर्थिक मदद की उम्मीद है। लेकिन खुद कर्ज में दबा सऊदी अरब पाकिस्तानी सेना की सेवाओं के बदले दो अरब डॉलर से ज्यादा शायद ही दे सके।

पाकिस्तान की सेना की भी सीमाएं हैं। वह अपनी पश्चिमी सीमाओं पर चल रहे विभिन्न विद्रोहों को निर्णायक रूप से खत्म नहीं कर पा रही है और न ही भारत के खिलाफ कोई सैन्य बढ़त हासिल कर सकती है। ऐसे में मुनीर के पास क्या है? उनकी प्रतिभा सैन्य कौशल में नहीं बल्कि अपनी सेना के नियंत्रण वाली राज्य-व्यवस्था की रूरर राजनीति को समझने में है। वह इसके जोखिम समझते हैं। यह सामन्त राजनीति नहीं है। इसे परिभाषित करने के लिए मेरे पास तीन विकल्प हैं। निर्दयी प्रतिस्पर्धा,

सरकार के भीतर भी यह समझ है कि आंदोलन को केवल ‘आरक्षण विरोध’ कहकर नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से पर्याप्त रणनीति नहीं होगी। संवाद शुरू होना ही इस आंदोलन की पहली राजनीतिक उपलब्धि है। लेकिन संवाद का अर्थ मांगों को स्वीकार करना नहीं है।

छठा यह कि, संविधान बनाम आंदोलन: असली सीमा कहां है? यहां सबसे जरूरी सावधानी है। आरक्षण व्यवस्था संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के विकसित होते न्यायशास्त्र से जुड़ी हुई है। इसलिए ‘आरक्षण’ इसे केवल सड़क के आंदोलन से समाप्त या पूरी तरह पुनर्गठित नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ लोकतंत्र में किसी नीति की आलोचना करने के लिए संविधान-विरोधी होना आवश्यक नहीं। यही लोकतांत्रिक संतुलन है- आरक्षण का संवैधानिक अस्तित्व सुरक्षित रहे, लेकिन आरक्षण की नीतियों पर लोकतांत्रिक समीक्षा का अधिकार भी सुरक्षित रहे। इसलिए ‘आरक्षण पर चर्चा ही नहीं हो सकती’ और ‘आरक्षण तुरंत खत्म कर दो’—दोनों अंतियां हैं।

सातवां यह कि, एससी/एसटी एक्ट को आरक्षण बहस में जोड़ना आंदोलन को कमजोर कर सकता है। जंतर-मंतर के कुछ प्रदर्शनकारियों ने एससी/एसटी एक्ट को समाप्त करने की मांग भी उठाई। राजनीतिक दृष्टि से यह आंदोलन के लिए जोखिम है। क्यों? क्योंकि आरक्षण की समीक्षा पर आर्थिक, प्रशासनिक और प्रतिनिधित्व आधारित बहस हो सकती है।

लेकिन एससी/एसटी एक्ट का विषय मुख्यतः अत्याचार, भेदभाव और कानूनी संरक्षण से जुड़ा है। दोनों को एक ही मुद्दा बना देने से आंदोलन का मुख्य प्रश्न—आरक्षण सुधार—एक अलग और अधिक विवादास्पद राजनीतिक लड़ाई में बदल सकता है। यदि आंदोलन व्यापक सामाजिक समर्थन चाहता है तो उसे अपने एजेंडे में स्पष्ट प्रार्थमिकता रखनी होगी।

आठवां यह कि, ‘मेरिट’ की बहस को भी अधिक वैज्ञानिक बनाने की जरूरत है। ‘मेरिट बचाओ’ एक प्रभावी नारा है। लेकिन मेरिट केवल परीक्षा में मिले अंकों का नाम नहीं है। एक गरीब परीक्षारी स्कूल का विद्यार्थी, जिसके पास महंगी कौचिंग, अंग्रेजी माध्यम, डिजिटल संसाधन और शिक्षित पारिवारिक वातावरण नहीं है, और दूसरी ओर अत्यधिक संसाधन वाले परिवार का विद्यार्थी—दोनों की परीक्षा-तैयारी की परिस्थितियां समान नहीं होतीं।

आज का इतिहास

- 1541 तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने बुडा और हंगरी को अपने कब्जे में लिया।
- 1883 इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 36 हजार लोगों की मौत हुई।
- 1910 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का युगोस्लाविया में जन्म हुआ।
- 1910 प्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का निधन हुआ था।
- 1914 बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर 50 माउजर और 46 हजार राउंड गोलियाँ लूटी।
- 1920 अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिला।
- 1934 प्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार तथा बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन का निधन हुआ था।
- 1955 सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली रिलीज हुई।
- 1972 यूनिवर्स (जर्मनी) में ओलिंपिक खेलों की शुरुआत हुई। इसी ओलिंपिक में इजराइली खिलाड़ियों पर हमला हुआ था।
- 1975 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा हिन्दुस्तानी सेवादल के संस्थापक एन. एस. हार्डिकर का निधन हुआ था।
- 1977 जर्मनी के म्यूनिख शहर में 20वें ओलिंपिक खेलों की शुरुआत।
- 1982 नासा ने टेलीसेट-एफ का प्रक्षेपण किया।
- 1988 म्यांमा की अहिंसावादी नेता आंग सान सू ची मोर्चा लेकर रंगून पहुंचीं।
- 1999 माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकार्ड बनाया।
- 2001 बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जेल भेजे गए।
- 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में दस दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू।
- 2007 पाक-अफगान सीमा पर अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने 12 तालिबानों को मार गिराया।
- 2008 तेलगु फ़िल्मों के सुपर स्टार चिरंजीवी ने अपनी नई पार्टी प्रजा राज्यम का उद्घाटन किया।
- 2012 प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार ए. के. हंगल का निधन हुआ था।
- 2013 फिलीपीन्स में विकास सहायता कोष घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन।
- 2015 अमेरिका के वर्जीनिया में दो पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
- 2017 गु्रमीतर राम रहीम पर कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में हुए प्रदर्शन में 31 लोग मारे गए।

भारतीयों को बेहतर प्रतिनिधित्व की जरूरत

शंकर अस्वर

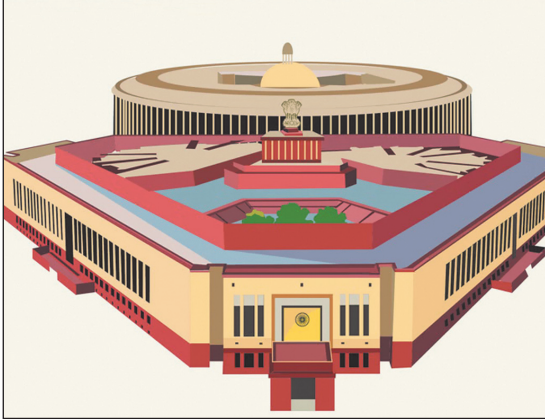
संसद के मानसून सत्र में 19 बैठकों में 11 बिल पास किए गए। इनमें से दस बिलों पर लोकसभा में कुल मिलाकर 64 मिनट का समय लगा। नौ बिलों के मामले में, सिर्फ़ उन्हें पेश करने वाले मंत्री ने ही बात की और कोई बहस नहीं हुई। निचले सदन में पूरे सत्र के दौरान प्रश्नकाल सिर्फ़ नौ मिनट चला, जो तय समय का महज एक प्रतिशत ही था, और मौखिक जवाब के लिए सूचीबद्ध किए गए 380 सवालों में से सिर्फ़ दो के जवाब दिए गए। इस खराब रिकॉर्ड की वजह से सांसदों की संख्या बढ़ाने की कोशिशों पर ध्यान गया है।

अजीब बात यह है कि इस सत्र में सरकार जिस एक बिल को पेश नहीं कर पाई, वह संसद के विस्तार से जुड़ा था, यानी ‘परिसीमन बिल, 2026’। यह बिल लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने वाला था, लेकिन यह राजनीति और आंकड़ों के फेर में उलझकर रह गया। लोगों के बीच चर्चा खर्च को लेकर है। इसमें अतिरिक्त सांसदों का खर्च (जिसका अनुमान 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है) रहने–सहने का खर्च, बजट आवंटन में बढ़ोतरी और निश्चित रूप से विधायकों की संख्या बढ़ने से होने वाला

अतिरिक्त खर्च वगैरह शामिल हैं। राज्यों को अलग–थलग महसूस कराने का खर्च भी है, क्योंकि वे इसे मुख्यधारा से खुद को दूर करने वाला कदम मानते हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है, जो हर सत्र के बाद उठती है कि क्या सांसद लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या पार्टियों का? क्या इससे कुछ बेहतर होगा?

चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि छोटे चुनाव क्षेत्रों का मतलब है–लोगों का ज्यादा करीबी प्रतिनिधित्व, और करीबी प्रतिनिधित्व का मतलब है बेहतर शासन–व्यवस्था। इस बात का पहला हिस्सा तो गणितीय है। दूसरा हिस्सा प्रतिनिधित्व से जुड़ा एक अनुभव–आधारित दावा है (चाहे वह लोगों का प्रतिनिधित्व हो या महिलाओं के अधिकारों का) और यह मौजूदा ढांचे तथा अब तक के कामकाज के रिकॉर्ड के आधार पर जो संभव है, उसके कहीं ज्यादा का दावा करता है। आखिर एक अतिरिक्त सदस्य असल में क्या कर सकता है। 7वीं अनुसूची रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, बैंकिंग और रेलवे को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रखती है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, भूमि और स्थानीय सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 10वीं



अनुसूची उस सदस्य को अयोग्य ठहराती है, जो अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है। दखल देने की गुंजाइश उस समय के राजनीतिक माहौल से सीमित होती है–इस सत्र में ‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव’ और ‘स्थगन प्रस्ताव’ की संख्या शून्य रही है।

माना जाता है कि बहुत छोटे इलाकों (स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों) में राजनीतिक प्रतिनिधित्व ब्रह्मांड से कामकाज बेहतर होता है। लेकिन, बेहतर नतीजों की यह धारणा बहस का विषय है। एनबीईआर के वेदा नरसिम्हन और जेफरी वीवर ने 1.5 लाख स्थानीय

सरकारों (पंचायतों) में 12 लाख बेहद स्थानीय प्रतिनिधियों का अध्ययन किया। नतीजा यह निकला कि मुख्य कामों, जैसे कार्यक्रम लागू करना और सरकारी पैसे की देखरेख, पर कोई खास असर नहीं दिखा। डेनिलो फ़ेरे की अगुआई में और ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस में छपे कई अध्ययनों के विश्लेषण में पाया गया कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि बाका आकार सरकारी बजट को किसी भी दिशा में बदलता है। ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात को अध्ययनों और शासन के ढांचे से चुनौती मिलती है।

संसद के हर सत्र में मंत्री खराब सेवाओं के लिए जवाबदेही से बचते हुए दिखते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून–व्यवस्था, शहर, पानी, खेती, जमीन और लेबर परमिट राज्य के विषय हैं। 307 और सांसदों के आने से नतीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा। वे वही सवाल 307 बार पूछेंगे और उन्हें वही जवाब मिलेगा। कानून बनाने की शक्ति के साथ–साथ खर्च

करने की शक्ति भी होती है। सबसे ज्यादा पैसा उन कामों के लिए रखा गया है, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। असल में, 191 बड़ी योजनाओं में से ज्यादातर (जिनमें प्रधानमंत्री से जुड़ी 29 योजनाएं भी शामिल हैं, जिन पर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होना है) राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों से जुड़ी हैं। नागरिकों की जिंदगी और रोजी–रोटी से जुड़ी लगभग हर परेशानी का समाधान राज्यों को करना चाहिए। लातपा कॉन्स्टेबल, जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिना शिक्षकों वाले सरकारी स्कूल, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, खाली पद, दूषित पानी की समस्या, कस्बों में दुर्गोी–बस्तियां, शहरों में बाढ़, खराब पानी आपूर्ति का फायदा उठाने वाला टैंकर माफिया, और म्युनिसिपल कस्बों में गाद और कचरा–ये सभी राज्यों से जुड़े मामले हैं।

850 सांसदों की मांग, मौजूदा 543 सांसदों के कामकाज के रिकॉर्ड के बिल्कुल उलट है। संविधान बनाने वालों ने केंद्र सरकार को संघ को मजबूत करने की शक्तियां दी थीं और राज्यों को विकास करने की जिम्मेदारियां सौंपी थी। समस्या यह है कि सत्ता की चाबी संसाधनों पर कब्जे में निहित है। केंद्र की सरकारों ने एक के बाद एक कई संशोधन

किए (जिनमें 42वां संशोधन सबसे बुरा था) और राज्यों को लगभग अपना उपनिवेश बना लिया। नीतियां दिल्ली में बनती हैं, और उन्हें लागू करने का काम राज्यों का होता है। खराब शासन की जड़ अधिकार और जवाबदेही के बीच का अलगाव है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीयों को बेहतर प्रतिनिधित्व की जरूरत है। जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व की जरूरत कहीं अधिक है। भारत की तरक्की का अगला चरण ढांचागत सुधारों पर निर्भर करता है। शुरुआत 42वें संशोधन को पलटने और 7वीं अनुसूची को उस मूल रूप में बहाल करने से होनी चाहिए, जिसकी कल्पना बाबा साहेब आंबेडकर व अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ने की थी।

हर बड़ा सुधार और कल्याणकारी विचार राज्यों से ही आया है। सरकार के तीसरे स्तर को फंड, काम और कर्मचारी देकर मजबूत करें। जब यह आधार तैयार हो जाएगा, तभी किसी भी स्तर पर ज्यादा प्रतिनिधियों की बात को सही ठहराया जा सकेगा। बिना ढांचागत सुधारों के सांसदों की संख्या बढ़ाने से राजनीतिक कमी तो पूरी हो सकती है, लेकिन विकास की कमी नहीं। प्रतिनिधित्व कोई संख्या नहीं है, यह एक शक्ति है। बिल में जो पेश किया जा रहा है, वह सिर्फ़ एक संख्या है।

जिनपिंग की भारत यात्रा– बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने का समय आ गया

संतोष कुमार पाठक

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। भारत यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। जिनपिंग इससे पहले वर्ष 2019 में शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। चीनी राष्ट्रपति के भारत यात्रा के दौरान जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर भी बातचीत होगी। हाल के दिनों में भारत चीन सीमा पर खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो खबरें आ रही है, उसने पूरे देश को चिंतित कर दिया है। बदले माहौल में अब भारत की कोई भी सरकार सिर्फ शांति और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के नाम पर पड़ोसी देश की इस तरह की नापाक हरकतों को उठे बस्ते में नहीं डाल सकती है। ऐसे में नई दिल्ली में स्वागत की तैयारियों से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत–चीन सीमा पर सैनिकों को पूरे साजो–सामान के साथ 24 घंटे रेडी मोड में रखना। चीन का इतिहास भी यही बताता है कि भारत को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

भारत–चीन संबंधों के बीच सबसे बड़ी विडंबना शीर्ष नेताओं के दौरों के दौरान या दौरे के आसपास ही शुरू होती है। आमतौर पर जब भी किसी दो देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यात्रा की कोई योजना बनती है तो दोनों ही देश, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान तो कम से कम कहीं कोई तनाव न पैदा हो। लेकिन चीन इसके बिल्कुल उल्टा करता है। चीन का इतिहास यह बताता है कि भारत की तरफ से संबंध सुधारने के लिए जब भी शीर्ष स्तर पर कोई नेता चीन जाता है या फिर भारत के निमंत्रण पर जब भी चीन से कोई शीर्ष नेता भारत आता है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनयिक शिष्टाचार को पूरी तरह से भत्ता बंटाते हुए चीन की सेना सीमा पर खुराफात शुरू कर देती है। एक तरफ शीर्ष स्तर पर बातचीत, शांति और व्यापारिक संबंधों के ढोल बज रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना भारत के क्षेत्र में जबरदस्ती घुसपैठ करने और भारतीय सेना से लड़ती–भिड़ती नज़् आती है। आपको बता दें कि,

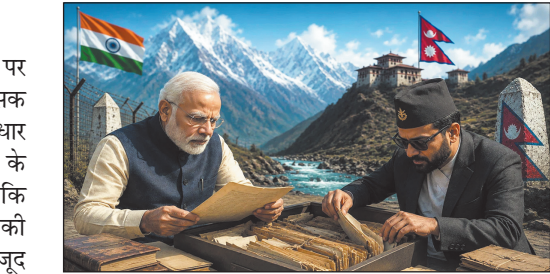
अब भारत के साथ नेपाल कैसे सुलझायेगा सीमा विवाद?

नीरज कुमार दुबे

तो कर लो बात! सीमा विवाद को लेकर भारत पर लगातार सवाल उठाने वाला नेपाल खुद उस ऐतिहासिक दस्तावेज की मूल प्रति नहीं ढूँढ पा रहा है, जिसके आधार पर उसकी सीमाओं की बुनियाद तैयार हुई थी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में स्वीकार किया है कि सरकार को यह तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि 1816 की सुगौली संधि की आधिकारिक मूल प्रति उसके पास मौजूद है या नहीं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में कुछ संबंधित दस्तावेज होने की जानकारी जरूर है, लेकिन वे वास्तविक आधिकारिक संधियाँ हैं या उनकी प्रतियाँ, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर विवाद फिर सुर्खियों में है। दरअसल, भारत और चीन के बीच लिपुलेख व्यापार मार्ग को फिर खोलने पर सहमति के बाद नेपाल ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा दोहराया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस ऐतिहासिक संधि को सीमा निर्धारण के बुनियादी कड़ी माना जाता है, उसकी मूल प्रति ही नेपाल के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, तो उसके सीमा संबंधी दावों की ऐतिहासिक और दस्तावेजी मजबूती को किस आधार पर परखा जाए?

सुगौली संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई वह ऐतिहासिक संधि थी, जिसने 1814–16 के एंग्लो–नेपाल युद्ध का अंत किया और नेपाल की क्षेत्रीय सीमाओं तथा ब्रिटिश भारत के साथ उसके संबंधों को बड़े पैमाने पर निर्धारित किया। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई और 4 मार्च 1816 को इसकी औपचारिक पुष्टि हुई। युद्ध में पराजय के बाद नेपाल को बड़े भूभाग से अपने दावे छोड़ने पड़े और उसकी पश्चिमी सीमा के निर्धारण में महाकाली नदी की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। इसी संधि को आगे चलकर नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा–व्यवस्था की आधारभूत कड़ी माना गया। यही कारण है कि सुगौली संधि की मूल



प्रति का गायब होना महज किसी पुराने कागज का गुम होना नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका सीधा संबंध सीमा, संप्रभुता और ऐतिहासिक भूगोल से जुड़ा है। खासकर तब, जब नेपाल आज उसी ऐतिहासिक सीमा–व्यवस्था के आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर अपना दावा करता है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि नेपाल में ऐतिहासिक संधियों के मूल दस्तावेजों की उपलब्धता को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। 2016 में भारत–नेपाल संबंधों की समीक्षा के लिए गठित प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह की चर्चाओं के दौरान 1950 की भारत–नेपाल शांति एवं मैत्री संधि की मूल प्रति खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं मिली। बाद में संसदीय जांच में सुगौली संधि और 1950 की संधि, दोनों की मूल प्रतियां नेपाल में नहीं मिलने की बात सामने आई। 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी कहा था कि मंत्रालय के पास दोनों संधियों की प्रतियाँ हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ॉरेंसिक जांच जरूरी है कि वे मूल दस्तावेज हैं या नहीं। नेपाल ने भारत और ब्रिटेन में उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों और नक्शों को भी तलाशने की बात कही थी। यानी सवाल केवल यह नहीं कि दस्तावेज कहाँ हैं, बल्कि यह भी है कि नेपाल के पास मौजूद प्रतियाँ कितनी प्रामाणिक हैं। इतिहास वैसे इससे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि नेपाल का हर सीमा दावा स्वतः गलत हो जाता है। सीमा विवादों का निर्धारण केवल किसी एक मूल दस्तावेज से

नहीं होता; ऐतिहासिक नक्शे, नदी की वास्तविक धारा, प्रशासनिक नियंत्रण, पुराने सरकारी रिकॉर्ड और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन नेपाल के लिए समस्या यह है कि जिस ऐतिहासिक संधि को वह अपनी सीमा–व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण मानता है, उसकी मूल प्रति के अस्तित्व पर ही उसकी सरकार स्पष्ट नहीं है। यही तथ्य उसके आक्रामक सीमा–रुख पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि नेपाल के पास मूल संधि उपलब्ध नहीं है और उसे अपनी प्रतियों की प्रामाणिकता तक फ़ॉरेंसिक तरीके से जांचनी पड़ रही है, तो सीमा विवाद पर निर्णायक और एकतरफा ऐतिहासिक दावे करना निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लिपुलेख क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन, तीनों के लिए संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र है।

दिलचस्प बात यह है कि इसी तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात कर दोनों के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और साझा हितों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं सुगौली संधि की मूल प्रति नहीं मिलने संबंधी नेपाली विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि दोनों देशों के लंबित मुद्दों को मौजूदा राजनयिक माध्यमों से सुलझाया जा सकता है।

बहरहाल, नेपाल यदि सीमा विवाद को वास्तव में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सुलझाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने अभिलेखों की स्थिति साफ़ करनी होगी। सुगौली संधि की मूल प्रति कहाँ है, मौजूद है या नहीं, और उसके पास उपलब्ध प्रतियां कितनी प्रामाणिक हैं, इन सवालों का जवाब देना जरूरी होगा। क्योंकि सीमा का फैसला नारों और राजनीतिक दावों से नहीं, प्रमाणित दस्तावेजों और स्थापित तथ्यों से होता है और फिलहाल, सुगौली संधि की मूल प्रति को लेकर नेपाल की अपनी स्वीकारोक्ति उसके दावे की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न जरूर खड़ा करती है।

योगेंद्र योगी

जिस देश में करोड़ों लोगों को साफ पीने का पानी, पर्याप्त बिजली, राशन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं, वहां सिर्फ आम लोगों की भलाई के नाम पर संसद में हंगामा करके अरबों रूपए स्वाह कर दिए जाते हैं। संसद में अब तक मानसून सत्र के दौरान हंगामे और व्यवधान के कारण लोकसभा में 7,023 मिनट का समय बर्बाद हो। अर्थात प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च का अनुमान हुआ। यह आंकड़ा करीब 175 करोड़ रुपए बैठता है। देश के लोकतंत्र का मंदिर है संसद, जहां पर जनता की, उनके अधिकारों, मुद्दों की आवाज़ गुंजनी चाहिए। लेकिन वहां अभी तक के मानसून सत्र में सिर्फ शोर सुनाई दिया। विपक्ष का हंगामा कान के पर्दों को फाड़ रहा है। सवाल ये है कि इस शोर का बिल कौन भर रहा है ? तो जवाब है–देश की जनता। क्योंकि संसद में हर मिनट हंगामा होता है तो सिर्फ बहस नहीं रुकती, बल्कि करीब ढाई लाख रुपये भी पानी की तरह बहते रहते हैं।

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर नीट पेपर परीक्षा, राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मामलों में गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कई दिनों तक हंगामा किया। जिससे संसद की कार्यवाई बाधित होती रही। संसद में विधायी कामकाज नहीं हो सका। संसद की कार्यवाई कई बार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सबसे अहम बात ये कि सदन स्थगित होने पर भी ये खर्च रुकता नहीं है। संसद की सुरक्षा, वहां के कर्मचारी, तकनीकी व्यवस्था और पूरा संसदीय तंत्र उसी तरह चलता रहता है। इसलिए जब कार्यवाही बार–बार बाधित होती है, तब करोड़ों रुपये का बोझ सीधे जनता की जेब पर पड़ता है।

संसद की कार्यवाही एक दिन के लिए अगर स्थगित होती है तो इसके पीछे 9 करोड़ रुपये का घाटा होता है। इस रकम को प्रति घंटे और प्रति मिनट के आधार पर यह प्रति घंटे एक करोड़ पचास लाख यानी डेढ़ करोड़ होती है। यह आंकड़ा इस साल के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पीठासीन स्पीकर जगदीबका पाल ने दिया था। साल 2014 से लेकर 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो बार–बार सदन के स्थगित होने की वजह से सरकारी तिजोरी का करीब 3300 करोड़ रुपया पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। संसद के इस तरह से बार–बार ठप होने पर ना सिर्फ जरूरी काम रुकते हैं, बल्कि लोगों के पैसे पर भी असर पड़ता है।

इसी तरह संसद के साल 2025 के मांसून सत्र दौरान



सांसदों ने देशहित की बजाय अपनी राजनीति में अधिक समय गंवा दिया। लोकसभा में सांसदों को 120 घंटे देश के मुद्दों पर चर्चा करनी थी, लेकिन वास्तव में सिर्फ 37 घंटे ही काम हुआ। अर्थात 83 घंटे बेकार गए। केवल 31ब काम हुआ और बाकी 69% समय सांसदों की आपसी राजनीति और हंगामे में बर्बाद हो गया। राज्यसभा का भी यही हाल था। यहां भी 120 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 47 घंटे ही काम किया गया। मतलब 73 घंटे बर्बाद हो गए। राज्यसभा में भी सांसदों ने सिर्फ 38ब काम किया। लोकसभा में 83 घंटे काम नहीं हुआ, जिससे लगभग 124 करोड़ 50 लाख रुपये जनता के पैसे बर्बाद हो गए। वहीं राज्यसभा में 73 घंटे की बर्बादी से करीब 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पिछले मानसून सत्र में दोनों सदनों में मिलाकर कुल 204 करोड़ 50 लाख रुपये बर्बाद हो गए। यह पैसा जनता के काम पर खर्च हो सकता था, लेकिन हंगामे और राजनीति की वजह से व्यर्थ चला गया।

संसद के चलने में करोड़ों के इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा अर्थात करीब 35 से 40 प्रतिशत खर्च इन्हीं सांसदों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं पर होता है जो संसद में खड़े होकर चीखते हैं, हंगामा बरपाते हैं, बिलों की पेश तक नहीं होने दे रहे। इन सांसदों को एक लाख रुपये मासिक वेतन, 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60 हजार रुपये कार्यालय और सहायक खर्च दिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली आने पर प्रतिदिन 2 हजार रुपये का विशेष भत्ता और यात्रा सुविधाएं भी मिलती हैं।

संसद सचिवालय के हजारों कर्मचारियों पर करीब 25 से 30 प्रतिशत खर्च होता है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, रिपोर्टर, ट्रांसलेटर, रिसर्च स्टाफ, स्टेनोग्राफर, मार्शल, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मचारियों का वेतन शामिल है। करीब 20 प्रतिशत खर्च संसद की हाई–टेक व्यवस्थाओं पर होता है। बिजली–पानी, संसद टीवी की लाइव ब्रॉडकास्टिंग, हाई–एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम, डिजिटल वोटिंग पैनल, साथ में इनका खाना–पीना और रोज छपने वाले

क्या ‘दिमागी नक्सलवाद’ ज्यादा खतरनाक है?

रवि रमेशचंद्र

हिंसक अराजकता और संविधान के विरोध को बौद्धिक समर्थन देने वाले ‘दिमागी नक्सल’ होते हैं। 15 अगस्त 2026 को अपने 12वें भाषण में लाल किले की प्राची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों से दिमागी नक्सलवाद से बचने की अपील की। दिमागी नक्सल आम नक्सलियों की तरह जंगल में हथियार लेकर नहीं घूमते बल्कि ये हमारे आस–पड़ोस में ही रहकर, लोगों को संविधान, सरकार और समाज के प्रति भड़काते हैं। ये लोगों को अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्हें भ्रमित करते हैं। इस शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो सीधे हथियार नहीं उठाते, बल्कि वामपंथी उठावाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। सरकार और समर्थकों का मानना है कि ये लोग जटिल नैरेटिव घड़कर युवाओं को गुमराह करते हैं। चूंकि यह एक वैचारिक स्रोत है, इसलिए ज्यादा खतरनाक भी है।

विचार शाश्वत होते हैं। व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं। विचारों में पुनः व्यक्ति निर्माण की क्षमता होती है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के व्यक्ति और संगठनों को जन्म दे सकते हैं। वामपंथी आतंकवाद, को नक्सलवाद का नाम दिया गया है। एक राज्य और समाज के विरुद्ध छेड़ा गया अराजक विद्रोह है, जिसकी कुछ राजनीतिक मंजुं और मान्यताएं भी हैं। इसकी कार्य पद्धति भी आतंकवादी संगठनों जैसी ही है। नक्सलवाद का बीजारोपण लोगों के दिमाग में सबसे पहले किया जाता है। मार्च 2026 को लक्ष्य बनाकर गृहमंत्री अमित शाह ने जंगली नक्सलवाद की कमर तोड़ दी, अब वह लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन दिमागी नक्सल वे रक्तबीज हैं जो फिर से नए हाथों में बंदूक थमा देंगे।

नक्सली आतंकवाद दोमुंहे सांप की तरह है। जिसका एक सिर तो जंगलों में रहकर राज्य,

संविधान, सरकार और समाज के विरुद्ध सशस्त्र हिंसा में लिस होता है, तो दूसरा सिर शहरी समाज में घुल–मिल जाता है। वे आम जीवन जीते हुए, ज्यादातर सरकारी खजाने से वेतन, अनुदान या अन्य प्रकार का मानधन लेकर बड़ी मौज का जीवन जीते हैं। ये ‘व्हाइट कॉलर’ रोजगार को अपना लक्ष्य बनाते हैं। इन्हें आप डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, जज, एन.जी.ओ. संचालक और कार्यकर्ता, वामपंथी राजनीतिक झुकाव वाले नेता जैसे किसी भी रूप में छुपकर नक्सलियों को बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहायता, सूचना और नैटवर्क उपलब्ध करावते हैं। चूंकि ये प्रत्यक्ष सशरीर नक्सलवाद में शामिल नहीं होते, इसलिए ये अपने दिमाग में हिंसा, हत्या, पड़ोय, बौद्धिक स्वीकृति निर्माण करने का कार्य करते रहते हैं। ये बड़ी होशियारी से लोगों की भावनाओं को तोड़ कर उन्हें नाटक, कविता, कहानी, चर्चा मंडलों, गोष्ठियों इत्यादि कला और बौद्धिक माध्यमों से आकर्षित करते हैं। चूंकि उपरोक्त समाज का अभिन्न अंग हैं तो आम जन को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। इसी को दिमागी नक्सलवाद कहा जाता है। ये जंगल में लड़ रहे नक्सली से ज्यादा खतरनाक हैं। इस बात को नकारना नहीं है कि अभी तक हमारी सरकारों ने समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में सफलता नहीं पाई है। मुख्यधारा की लोकतांत्रिक राजनीति ने सत्ता का दुरुपयोग करके गरीब, किसान, मजदूर, वनावासी समुदायों के साथ बड़ा अन्याय किया है। प्रशासन तंत्र उनके रक्षक कम, भक्षक अधिक हैं। आकट भ्रष्टाचार में डूबा लोकतंत्र आमजन के लिए बेमानी साबित होता है। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य वोट पाकर सत्ता पाना भर रह जाने से लोकतंत्र के विकास का फल कुछ धनी, उद्योगपतियों और सत्ताधारी लोगों तक सीमित रह जाता है। यह भी उतना ही खतरनाक है, जितनी नक्सल हिंसा।

सावन में वयों पहननी चाहिए हरी चूड़ियां, क्या है इस रंग को उपयोग करने के लाभ



सावन की रिमझिम के साथ हर तरफ हरियाली छा जाती है। जिधर भी नजर दौड़ा कर देखा जाए प्रकृति के सौन्दर्य का दर्शन होता है। कुदरत के बदले स्वरूप के साथ महिलाओं के श्रृंगार में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रकृति से एकाकार होने के लिए वह हाथों में हरी मेंहदी रचाती हैं, हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां धारण करती हैं। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सावन के महीने में हरे रंग का अधिक से अधिक उपयोग करने से सोया भाग्य जागृत होता है। हिंदू शास्त्रों में प्रकृति को परमात्मा का दर्जा दिया गया है इसलिए उसका पूजन करने का विधान है। ज्योतिषी विद्वान मानते हैं कि हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक है।

सावन माह में सुहागिनों के बहुत सारे पर्व आते हैं, जिनमें कज्जली तीज और हरियाली तीज मु्य हैं। इन पर्वों पर हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और मेंहदी लगाने का नियम प्राचीनकाल से ही चला आ रहा है। इससे श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति-पत्नी के संबंध प्रगाढ़ बनते हैं।

हरे रंग का संबंध बुद्ध ग्रह से है। उनके शुभ प्रभाव से व्य्क्ति की जीविका में उतार-चढ़ाव आते हैं। करियर और व्यापार में शुभता के लिए इस महीने में अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग करके बुद्ध देव को प्रसन्न करें। जो सुहागन महिलाएं ऐसा करती हैं उनके घर में सेपन्नता और धन-धान्य बढ़ता है।

जो लोग सावन में हरा रंग धारण करते हैं, भगवान शिव उन पर विशेष अनुकंपा बरसाते हैं। सावन में प्राकृतिक सामग्री से शिव पूजन किया जाता है, जिससे भोले बाबा खुश होते हैं। जो लोग स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं, वह शिव जी के प्रिय बन जाते हैं। जो महिलाएं सावन माह में हरे रंग की चूड़िया पहनती हैं, श्री हरि विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं।

सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए हरा रंग खास भूमिका निभाता है। पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास भरने के लिए बेडरूम के दक्षिण पूर्व हिस्से को हरे रंग से पुतवाएं।



ीतिष शास्त्र: ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत प्रत्येक

गुघ को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जो उनके ग के आधार पर निर्धारित है । ये तीन श्रेणियां हैं देव ग, मनुष्य गण और राक्षस गण। गण के आधार पर गुघ का स्वभाव और उसका चरित्र भी बताया गया ।

गुघ गण: वही जिन लोगों का संबंध मनुष्य गण से ता है । वह धनवान होने के साथ ही धनुर्विद्या के अच्छे नकार होते हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े होते हैं । साथ ही ः समाज में काफी सम्मान पाते हैं । और लोग उसकी त को ऊपर रखकर चलते हैं ।

क्षण गण: लेकिन जब बात आती है राक्षण गण की बहुत से लोग इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं । लेकर भ्रातियां गढ़ने लगते हैं । जोकि कदापि सही नहीं है । हा इसकी खूबियां थोड़ी अलग और विशिष्ट है ।

भाजपा फैलाएगी पीएम मोदी की सप्तधारा : संबित पात्रा



नईदिल्ली। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में बताए गए विकास के सात रास्तों यानी सप्तधारा की तारीफ की और कहा कि अब भारत के सामने विकास का एक लक्ष्य है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पात्रा ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब सही नेता सही समय पर सही लक्ष्य चुनता है। उन्होंने सप्तधारा को हासिल करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले दिनों में सप्तधारा का संदेश फैलाएगी ताकि प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए लक्ष्य की बारीकियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। भाजपा नेता ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने सप्तधारा के बारे में बात की थी। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य की जरूरत होती है। किसी भी देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब सही नेता सही समय पर सही लक्ष्य चुनता है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे सरकारी नियुक्ति पत्र



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 के पहले यह परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। आदित्यनाथ यहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से कृषि विभाग के लिए नव चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों (समूह-ग) एवं मंडी परिषद में श्रेणी-तीन, वर्ग-दो के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्रों का वितरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया उप्र में पिछले साढ़े नौ वर्षों में हमारी सरकार ने नौ लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि अगले छह माह के अंदर एक लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस



नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी लोकसभा सांसदों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी। टीएमसी के 20 सांसदों के कथित तौर पर दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थीं। हालांकि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अयोग्यता की याचिकाओं पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और स्पीकर से मांग की कि वे संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बागी सांसदों के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर फैसला दें। यह अनुसूची दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े अन्य पक्षों, जिनमें 20 बागी सांसद भी शामिल थे, को नोटिस जारी किए।

महिला अधिकारों पर घमासान! राहुल से डरी हुई है भाजपा



मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बचाव किया और पितृसत्ता और महिलाओं के अधिकारों पर गांधी के बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की आलोचना की। राउत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को कभी किसी खास धर्म, खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कांग्रेस नेता से डरने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को कभी किसी एक धर्म, खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। वे राहुल गांधी से डरते हैं, इतना डरते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। किरेन रिजिजू बेशक संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन वे इतने बड़े नेता नहीं हैं कि राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें कहें। मैं किरेन रिजिजू से कहूंगा कि राहुल गांधी अब बहुत आगे निकल चुके हैं; वे आपके नियंत्रण से बाहर हैं।

आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला 3 सितंबर को



नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के टैंडर में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर अपना फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। एटी करणश्रम ब्रांच (एसबीबी) ने 18 अगस्त को पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को सत्येंद्र जैन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन के अलावा पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं, मामले के एक अन्य प्रमुख आरोपी और जल बोर्ड के पूर्व सचिवा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पूर्व मंत्री सतेेंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुराी और पंकज वर्मा शामिल हैं।

आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल पर घमासान

राहुल गांधी के आरोपों पर मंत्री अशोक उइके का पलटवार

मुंबई। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके आमने-सामने हैं। राहुल गांधी ने पुणे के आदिवासी छात्रावासों में 30 साल की उम्र सीमा, कथित प्रेग्नेंसी टेस्ट, असुरक्षित सुविधाओं और अन्य नियमों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। वहीं उइके ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को सही जानकारी नहीं दी गई और उनके आने से पहले ही छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। छात्रों की मांगों में सरकारी आदेश वापस लेना, उम्र सीमा खत्म करना या 36 साल करना, छात्रावास सुविधाओं में सुधार, गढ़चिरोली में सांप के काटने से जान गंवाने वाली तीन छात्राओं के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा पेसा एक्ट को सख्ती से लागू करने और आदिवासी नीतियां बनाने समय छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है।



उइके ने राहुल गांधी के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने आदिवासी छात्रावासों में छात्राओं के लिए प्रेग्नेंसी टेस्ट का आरोप लगाया था। मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक छुट्टी पर रहने वाले छात्रों से स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने की बात पूरी तरह गलत है और ऐसा कोई नियम या जांच नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल में रहने की उम्र सीमा को 30 साल तक बढ़ाया गया था। उइके ने राहुल गांधी पर

तंज कसते हुए कहा कि उनका मामला अलग है और वे किसी मुद्दे को कितनी भी बार शुरू करें, वह असफल ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी छात्रों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है और उनकी मांगों पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

आदिवासी आवासीय स्कूलों में सुविधाओं की कमी और सांप के काटने की घटनाओं को लेकर भी उइके ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में ऐसी घटनाएं हुई हैं या जहां अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनमें कुछ स्कूल कांग्रेस के पूर्व सांसद मारोतराव कोबासे और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. वसंत पुरके जैसे नेताओं से जुड़े हैं। उइके ने कहा कि ये सभी कांग्रेस नेता हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र के सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, महागठबंधन सरकार जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सक्षम है और व्यवस्था में सुधार का काम चल रहा है तथा आगे भी जारी रहेगा।

मंत्री ने राहुल गांधी पर राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी यात्राओं का दायरा झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल तक भी बढ़ाना चाहिए। उइके की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब आदिवासी छात्रों के आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, वहीं मंत्री अशोक उइके ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है।

दिल्ली प्रोटेस्ट मामले में शाह की भूमिका की जांच वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई के विरोध-प्रदर्शन के दौरान ज़रूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी को अपनी जांच जारी रखने दी जानी चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के पुनर्गठन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सरकार और पुलिस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका की व्यापक जांच की मांग की थी। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस अर्जी को जल्द लिस्ट करने की मांग की, जिसमें कमेटी के पुनर्गठन की अपील की गई थी। सीजेआई ने कहा कि अर्जी को लिस्ट किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा जो भी काम करेगा, वह इस कोर्ट की सीधी निगरानी में काम करेगा। हमने इस मामले का निपटारा नहीं किया है और हम हर चीज पर नजर रखेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कमेटी को अपना काम शुरू करने दें और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी कोई भी चिंता कोर्ट के सामने रखें। सीजेआई ने आगे कहा

कि कभी-कभी हमें कुछ सीमाओं, जैसे उपलब्धता और अन्य कारकों के दायरे में भी काम करना पड़ता है। आप सभी भी समिति की मदद के लिए मौजूद हैं और जब भी कोई चिंता हो, तो हमें बता सकते हैं। उन्हें काम करने दें और देखें कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अर्जी का विरोध करते हुए इसे शरारतपूर्ण बताया और कमेटी के पुनर्गठन की याचिकाकर्ताओं की मांग पर आपत्ति जताई। जब शंकरनारायणन ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल अर्जी को लिस्ट करने की मांग कर रहे थे, तो मेहता ने बताया कि इसमें उन जजों के नाम भी शामिल थे जिन्हें याचिकाकर्ता पैनल में चाहते थे, साथ ही कुछ मंत्रियों के खिलाफ जांच की मांग भी की गई थी।

सीजेआई ने शंकरनारायणन से कहा कि हमें जजों के नाम इस तरह से लेना पसंद नहीं है। इस दौरान, एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के मन में कुछ संदेह थे, लेकिन जोर देकर कहा कि वे एक साझा मकसद के लिए काम कर रहे थे। हालांकि, मेहता ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं को हर किसी और सभी संस्थानों के बारे में संदेह था और उन्होंने अर्जी को निश्चित रूप से उचित नहीं बताया।

जनगणना में जाति गिनने के तरीके पर घमासान

खरगे-राहुल का पीएम मोदी को पत्र पूछा- सही डाटा कैसे मिलेगा?

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने जातियों का विवरण दर्ज करने के लिए अपनाए गए ओपन-एंडेड सवाल के तरीके पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे देश में जातियों की वास्तविक संख्या का सही आकलन नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि एक ही जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से पहचानी जाती है। ऐसे में यदि लोग अपनी जाति अलग-अलग नामों से दर्ज कराएंगे, तो एक ही समुदाय के आंकड़े कई हिस्सों में बंट जाएंगे और पूरी जाति जनगणना का डेटा अव्यवस्थित हो सकता है। खरगे और राहुल गांधी ने मांग की है कि मौजूदा प्रश्नावली को रद्द कर प्रमाणित जाति सूची के आधार पर इस प्रश्नावली तैयार की जाए और इसके लिए राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों तथा आम लोगों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाए।

दोनों नेताओं ने पत्र में कहा कि भारत में सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियां सही और विश्वसनीय आंकड़ों के बिना प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जा सकतीं। अलग-अलग जातियों की आबादी और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है, जब उनकी संख्या भी सटीक तरीके से दर्ज हो। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, मौजूदा प्रक्रिया में प्रत्येक



व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, वही दर्ज किया जाएगा। इससे सामने आने की आशंका है और देश में जातियों की संख्या वास्तविकता से कहीं अधिक दिखाई दे सकती है।

खरगे और राहुल ने चेताया कि गलत या बिखरे हुए आंकड़ों का सबसे ज्यादा असर ओबीसी, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों पर पड़ेगा। जब किसी समुदाय की वास्तविक संख्या ही सामने नहीं आएगी, तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन भी मुश्किल होगा। इसका असर शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि मौजूदा जनगणना प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है, ऐसे में देश में ओबीसी की वास्तविक आबादी का पता लगाना और भी मुश्किल होगा।

कांग्रेस नेताओं ने जातियों की पहचान के लिए पहले से तैयार और प्रमाणित सूची के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना में इसी तरह की सूची का इस्तेमाल किया जाता है। उनके अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की मौजूदा सरकारी सूचियों तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के आधार पर जातियों की एक प्रमाणित सूची तैयार की जा सकती है। इसके बाद जनगणना में उसी सूची के आधार पर जाति दर्ज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

खरगे और राहुल गांधी ने पत्र में तेलंगाना और बिहार में किए गए जाति सर्वेक्षणों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में पहले से तैयार जाति सूचियों के आधार पर आंकड़े जुटाने का तरीका अपनाया गया था। दोनों नेताओं ने इन सर्वेक्षणों में इस्तेमाल की गई जाति सूचियों को अपने पत्र के साथ संदर्भ के लिए संलग्न करने की बात कही।

कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे मौजूदा तरीके से की जा रही जाति जनगणना को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने केंद्र सरकार से मौजूदा प्रश्नावली वापस लेने, राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से बातचीत करने तथा व्यापक सहमति के बाद नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की। उनका कहना है कि जाति जनगणना केवल कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें हर जाति और समुदाय की संख्या सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है, ताकि इसके आंकड़े सटीक, सार्थक और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए उपयोगी साबित हो सकें।

खेल प्रमुख समाचार

डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाना भारत के लिए आसान नहीं

मुंबई। भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में थोड़ा पीछे चल रही है और श्रीलंका में उत्साहजनक प्रदर्शन को न्यूजीलैंड दौरे में दोहराना आसान नहीं होगा। डब्ल्यूटीसी फाइनल में दो बार जगह बनाने वाली भारतीय टीम अभी अंशक तालिका में पांचवें स्थान पर है। उसे फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए अधिकतर मैच जीतने होंगे। अगले साल फाइनल में शीर्ष दो टीमों के बीच मुकाबला होगा।

भारतीय टीम जनवरी 2027 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले न्यूजीलैंड में दो टेस्ट मैच खेलेगी। भारत इस दौरे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे और उतने ही टी20 मैच भी खेलेगा। द्रविड़ ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने में सफल रहेगा। अगर भारत मौजूदा स्थिति के बावजूद फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेता है तो यह शानदार उपलब्धि होगी।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय टीम थोड़ा पीछे चल रही है। लेकिन भारतीय टीम बहुत शानदार है और उसे किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता। उसने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की, इसलिए पहला कदम बहुत अच्छा है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है और बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से दूसरे टेस्ट में भी उसका पलड़ा भारी है। अक्टूबर में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के बारे में द्रविड़ ने कहा कि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के अनुभव की कमी दोनों टेस्ट मैचों में महसूस की जाएगी। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घरेलू मैदानों पर खेलना हमेशा एक चुनौती होता है। न्यूजीलैंड की टीम कड़ी चुनौती पेश करती है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/प्रमुख समाचार

बाजार में लौटी रैनक, सेंसेक्स 286 अंक चढ़कर बंद

नईदिल्ली। भारतीय बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। जबकि सुबह बेंचमार्क इंडेक्स कमजोर खुले थे। एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 115 अंक चढ़कर 24,334 पर बंद हुआ है, जो कारोबारी सेशन में 24,115.45 तक फिसला था। बीएसई सेंसेक्स भी 286 अंकों की मजबूती के साथ 77,656 पर बंद हुआ है। इंडेक्स में 77,125 के निचले स्तरों से 500 अंकों से ज्यादा की रिकवरी दर्ज की गई। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू बैंक, फार्मा जैसे सेक्टर में देखने को मिली। घरेलू बाजारों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। बाजार में जोश भरने का काम ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेतों ने किया। इसके अलावा लगातार 2 दिनों से बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशकों की ओर से लौटी खरीदारी है, जो सोमवार को 1,181.66 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीदारी की।

मोबाइल उत्पादन और निर्यात लक्ष्य को झटका

नईदिल्ली। मोबाइल के संबंध में देश की महत्ववांकांक्षी योजना की कल्पना साल 2022 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडिया सेल्युलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) की साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिकी के परिकल्पना दस्तावेज में की गई थी। इसके तहत वित्त वर्ष 26 तक 126 अरब डॉलर का उत्पादन मूल्य हासिल करना था जिसमें से 52 से 58 अरब डॉलर का योगदान निर्यात का होता। लेकिन यह लक्ष्य हासिल करने में भारत को 5 साल लग सकते हैं। वित्त वर्ष 26 में मोबाइल के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के 5 साल पूरे हो गए। इसके साथ ही उद्योग 75 अरब डॉलर का उत्पादन करने में कामयाब रहा है। इसमें से 29 अरब डॉलर की राशि निर्यात से हासिल हुई। इसमें 68 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा ऐपल ईक के निर्यात का रहा।

जापान के साथ बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय

तोक्यो। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि जापान के साथ बढ़ता व्यापार घाटा भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए जापान में भारतीय प्रमाणपत्रों को अधिक मान्यता देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कड़े प्रमाणन और नियामकीय मानदंड भी भारतीय निर्यातकों, खासकर जापानी बाजार में दवा कंपनियों के लिए प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं। गोयनका ने कहा कि जापान के साथ भारत का व्यापार मुख्य रूप से एक ही दिशा में बढ़ा है और भारतीय कंपनियों को जापानी बाजार तक पहुंच बनाने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह (व्यापार घाटा) चिंता का विषय रहा है। मुझे लगता है कि इस अवधि में हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है और विभिन्न बातचीत के दौरान मंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि व्यापार बढ़ा है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर 1,400 करोड़ का बड़ा निवेश

नई दिल्ली। फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन (फेडएक्स) दिल्ली हवाई अड्डे पर 2,30,000 वर्ग फुट में फैला हवाई मालवाहन केंद्र विकसित करने के लिए 15 करोड़ डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू की मौजूदगी में आज राष्ट्रीय राजधानी में इस सुविधा के निर्माण की आधारशिला रखी गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य भारत को हवाई मालवाहक परिवहन की रीढ़ बनना चाहिए। फेडएक्स ने प्रेस विज्ञापि में कहा कि एकीकृत हवाई मालवाहक केंद्र इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) स्थित जीएमआर कार्गो सिटी में बनाया जाएगा। इससे उत्तर एवं पूर्वी भारत के बीच संपर्क मजबूत होगा और कारोबारियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

राजेश्वरी सेनगुप्ता

कई लोगों की राय है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के तौर-तरीकों में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। उसे नीतिगत दरें तय करने का अपना तरीका तो बदलना ही चाहिए। संभव है कि उसे मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर कदम उठाने का तरीका ही छोड़ना पड़े। क्या इन दावों और तर्कों में कोई दम है?

असल में इन लोगों के तर्कों की बुनियाद कुछ इस तरह है। जब से रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लक्ष्य साधना शुरू किया है तब से वास्तविक ब्याज दरें बहुत अधिक रहने लगी हैं। ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक वृद्धि कम रह गई है। इसकी वजह रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जाने वाला एक गलत तरीका है। जब कीमतों में गिरावट शुरू होने वाली होती है तब भी वह पिछली मुद्रास्फीति के आधार पर ही दरें तय करता है।

ये दावे कुछ ज्यादा बड़े हैं और इन पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले मुख्य तर्क पर विचार कर लेते हैं, जिसके हिसाब से मुद्रास्फीति को आधार बनाने की वजह से रिजर्व बैंक का झुकाव सख्त मौद्रिक नीति की तरफ हो गया है। मगर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं।

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में मुद्रास्फीति एक निश्चित दायरे में रखने का लक्ष्य अपनाया है और तभी से वास्तविक रीपो दर (नॉमिनल रीपो दर में से समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति घटाने के बाद आई दर) औसतन 1.1 प्रतिशत ही रही है। भारत जैसी तेजी से बढ़ रहे देश के लिए यह बहुत कम है। यह उस तटस्थ दर से भी कम है, जो रिजर्व बैंक के हिसाब से 1.5 से 2 प्रतिशत है।

मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति के दायरे में रखने का लक्ष्य पाने के लिए यह

बहुत कम है क्योंकि 2015 से औसत मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत रही है। फिर ये लोग वास्तविक ब्याज दर ऊंची रहने की शिकायत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय के लिए और हाल-फिलहाल भी वास्तविक दरें वाकई 2 प्रतिशत से अधिक रही हैं। वर्ष 2025-26 में वास्तविक दर 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिजर्व बैंक का ढांचा केवल पिछली मुद्रास्फीति पर ध्यान देता है, जैसा दावा कुछ टिप्पणीकार करते हैं? बॉस्टन फेड की वैशाली गर्ग और मैंने आंकड़ों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया (वी गर्ग और आर सेनगुप्ता, ‘टू एक्शनस मैच वर्ड्स? रीअसेसिंग दि टेलर रूल इन एन इमर्जिंग-मार्केट कॉन्टेक्स्ट’, फेडरल रिजर्व बॉस्टन वर्किंग पेपर्स,



अगस्त 2026)। हमने पाया कि रिजर्व बैंक रीपो दर तय करते समय पिछली मुद्रास्फीति दर ध्यान में रखता है। मगर यह मुद्रास्फीति के बारे में अपने अनुमान को भी काफी तक्ज्जो देता है, जो मुद्रास्फीति को तय दायरे में रखने के लिए जरूरी है।

इसलिए समस्या ढांचे के साथ नहीं, पूर्वानुमान की सटीकता के साथ है। अगर मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बहुत अधिक है तो वास्तविक दर भी बहुत अधिक होगी और हाल ही में ऐसा ही हुआ। अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति के बाद जारी बयान में रिजर्व बैंक ने 2025-26 में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहने का अनुमान जताया था। वास्तविक मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक ने दिसंबर के बयान तक अपना अनुमान उस स्तर तक कम नहीं किया। अच्छी नीयत

से गलत पूर्वानुमान जताने का नतीजा वही होता है, जिसकी बात कुछ लोग करते हैं ड़् बाद में पता चलता है कि वास्तविक दरें बहुत सख्त थीं या बहुत नरम।

रिजर्व बैंक यह बात जानता है और इसीलिए वह बहुत व्यावहारिक है। असाधारण दौर में जब मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि की दिशा काफी हद तक साफ होती है तो मौद्रिक नीति अधिक आक्रामक हो सकती है। उदाहरण के लिए जब कोविड महामारी आई तो साफ था कि मांग कम हो जाएगी। इसलिए रिजर्व बैंक को रीपो दर बहुत कम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सामान्य दौर में रिजर्व बैंक नए पूर्वानुमानों पर प्रतिक्रिया देने में सतर्क रहा है। उसने रीपो दर 5.25 से 7 प्रतिशत के सीमित दायरे में रखी है जो मुद्रास्फीति के दायरे (2 से 6.8 प्रतिशत) से अधिक सख्त है। यह बात समझ में आती है।

किसान समृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक कदम

2.5 वर्षों में किसानों के खातों में पहुंचे डेढ़ लाख करोड़ रुपए

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पूर्व एकमुश्त प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत बीते तीन वर्षों में किसानों को धान मूल्य अंतर की राशि के रूप में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।



हमारी सरकार का लक्ष्य है - किसान का सम्मान, उसकी समृद्धि और उसका संपूर्ण आर्थिक सशक्तीकरण।
- श्री विष्णु देव मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

“

हमारी सरकार का संकल्प है कि देश का हर किसान समृद्ध बने, आधुनिक तकनीक अपनाए और खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जाए।

- श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से **26 लाख** किसानों को लाभ

- राज्य के 26 लाख किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर मिल रहा है।
- विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के 32 हजार 500 किसान भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

सीधा लाभ सीधा सम्मान

राशि प्राप्त हुई 10000 रुपए आपके खाते में DBT के माध्यम से भेजी गई है।



सुशासन दिवस पर ऐतिहासिक उपहार की हुई थी शुरुआत

सरकार बनाने के बाद अटल जी के जन्मदिवस 26 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने अपनी एक और गारंटी को पूरा करते हुए 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया। यह किसानों के परिश्रम और सरकार की प्रतिवद्धता के संगम का प्रतीक था।

₹3716 करोड़
धान बोनस अंतरित



धान खरीदी में नया रिकॉर्ड

- विपणन वर्ष 2024-25 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की।
- किसानों को 34,500 करोड़ रुपए की समर्थन मूल्य राशि का तत्काल भुगतान किया गया।
- 12 जनवरी 2025 को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 25 लाख 49 हजार किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की अंतर राशि का एकमुश्त अंतरित किया गया।



किसानों के खातों में पहुंचे डेढ़ लाख करोड़ रुपए

बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में लगभग

₹1,50,000 करोड़ रुपए

की राशि का सीधा अंतरण किया गया है। यह किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण का स्पष्ट उदाहरण है।



बीज उपलब्धता के लिए नीति सुधार

राज्य मंत्रीपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में संशोधन कर बीज उपलब्धता प्रणाली को और सशक्त बनाया गया है।

अब बीज का उपार्जन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा।

आवश्यकता पड़ने पर सहकारी समितियों, नाफेड, मध्यप्रदेश बीज महासंघ और भारत सरकार द्वारा चयनित केंद्रीय नोडल एजेंसियों से भी बीज क्रय किया जाएगा।



रिकॉर्ड धान खरीदी



किसान का परिश्रम, सरकार का समर्थन



खुशहाल किसान, समृद्ध छत्तीसगढ़

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

25 मार्च 2026 को लगभग 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को **500 करोड़ रुपये** की राशि प्रदान किया गया।



योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए 495.96 करोड़ रुपये का प्रावधान।



प्रत्येक पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में।



यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हितग्राहियों को दी जाती है।

जिलेवार प्रमुख लाभार्थी आंकड़े

रायपुर	53,338 (सर्वाधिक)
विलासपुर	39,401
महासमुंद	37,011
बीजापुर	1,542 (सबसे कम)
कोरिया	1,549
नारायणपुर	1,805

योजना के उद्देश्य

- भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना
- ग्रामीण गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ना
- 'अंत्योदय' की भावना के तहत अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना
- भूमिहीन परिवारों की आय में वृद्धि, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना



बजट प्रावधान

संकल्प बजट 2026-27 में योजना के लिए **600 करोड़ रुपये** का प्रावधान।

किन-किन को मिलता है लाभ



भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार



वनोपज संग्राहक परिवार



चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक कार्य करने वाले



पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार



अनुसूचित क्षेत्रों के पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवार



लाभार्थी सूची में **22,028** बैगा और गुनिया परिवार शामिल

विशेष तथ्य



पहले दी जाने वाली 7,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया



योजना से परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों में सहायता

किसान खुशहाल - छत्तीसगढ़ खुशहाल